

जब तक जीना, तब तक
सीखना, अनुभव ही जीवन
में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

वर्ष 02, अंक 170, नई दिल्ली। शुक्रवार, 30 अगस्त 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

03 दिल्ली के हेल्थ प्रोफेशनल ने निकाला न्याय मार्ग

06 खेल भावना में 'राष्ट्र प्रथम' सर्वापरि रहे

08 कुलपति प्रो करुणेश सक्सेना ने दिए सफलता के मंत्र

दिल्ली की परिवहन व्यवस्था और महिला सुरक्षा: एक नजर

जान्हवी भल्ला

आज के समय में दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में, जहां लाखों लोग रोजाना बस, मेट्रो और अन्य सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, वहां महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह चिंता सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी यह एक बड़ी समस्या है।

दिल्ली में, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन इन प्रयासों का असर कितना हुआ है, यह विचारणीय है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं और नीतियां बनाई गई हैं,

जैसे कि महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित सीटें, महिला सवारियों के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र, और पुलिस की तैनाती। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद, महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं में कोई खास कमी नहीं आई है।

एक अध्ययन के अनुसार, दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में से लगभग 50% ने एक से अधिक प्रकार की हिंसा का अनुभव किया है। यह आंकड़ा बताता है कि महिलाओं को न केवल शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है, बल्कि यौन और मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है।

इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। दिल्ली की

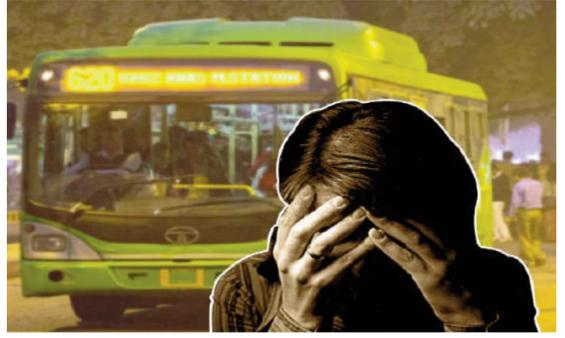
परिवहन व्यवस्था में भीड़-भाड़, अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, और संवेदनशीलता की कमी कुछ प्रमुख कारक हैं। इसके अलावा, कई बार महिलाओं को रात के समय सुरक्षित परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण भी जोरिखत उठाना पड़ता है।

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को और अधिक सख्त कदम उठाने की जरूरत है। शहरों को लिंग-संवेदनशील सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और नीतियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके। इसके लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित और आरामदायक परिवहन का प्रावधान किया जाना

चाहिए, जिसमें सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, और रात्रिकालीन सुरक्षा तंत्र शामिल हो सकते हैं।

इस दिशा में जागरूकता फैलाने और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जब तक हम सब मिलकर इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक महिलाओं की सुरक्षा एक चुनौती बनी रहेगी।

दिल्ली को एक सुरक्षित शहर बनाने के लिए हमें अपने प्रयासों को और मजबूत करना होगा, ताकि हर महिला बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सके।



सप्ताह में छह दिन चलेगी वंदे भारत, पीएम मोदी ए क सितंबर को दिखाएंगे हरी झंडी



मेरठ-लखनऊ के बीच चलने वाली वंदेभारत एक्सप्रेस का नया शेड्यूल जारी किया गया है। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी मंगलवार को छोड़कर। मेरठ से सुबह 6:35 बजे चलकर लखनऊ दोपहर 1:35 बजे पहुंचेगी। उद्घाटन दिवस 31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्युअल हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया जाएगा। ट्रेन में सफर करने वालों को फ्री यात्रा पास भी दिए जाएंगे।

गया है। ट्रेन का सप्ताह में छह दिन संचालन होगा। मंगलवार को नहीं चलेगी। नए शेड्यूल में आलम नगर (लखनऊ) का स्टॉपेज नहीं है। पहले शेड्यूल में ट्रेन को आलम नगर में भी रुकना था। मेरठ से रवाना होने का समय सुबह 6:35 बजे ही रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मेरठ से दोपहर 12:30 बजे वर्युअल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

पहले यह समय दोपहर एक बजे था। एक सितंबर से लखनऊ से ट्रेन का नियमित संचालन होगा। मुरादाबाद स्टेशन पर ट्रेन का भव्य स्वागत किया जाएगा। रेलवे ने 27 अगस्त को मेरठ-लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस (22490/22489) के संचालन की घोषणा

की थी। इसका समय तो जारी किया था, लेकिन नियमित संचालन को लेकर असमंजस था। एक सितंबर को लखनऊ से दोपहर 2:45 पर रवाना होगी।

बरेली में शाम 6:02, मुरादाबाद 7:32 और मेरठ रात 10 बजे पहुंचेगी। दो सितंबर को मेरठ से ट्रेन का संचालन होगा। वहां से सुबह 6:35 पर रवाना होगी, मुरादाबाद में सुबह 8:35, बरेली 9:56 और लखनऊ दोपहर 1:35 पहुंचेगी। 31 अगस्त को उद्घाटन के दिन फूलों से सजी ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को 12:30 रवाना करेंगे। 31 अगस्त को ट्रेन दोपहर 2:30 बजे मुरादाबाद पहुंचेगी।

इसके बाद बरेली 3:51 और लखनऊ शाम 7:40 बजे पहुंचेगी। इस अवसर पर ट्रेन का मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत होगा। स्टेशन पर भी सजावट की जाएगी। ट्रेन में सफर करने वालों को फ्री यात्रा पास भी दिए जाएंगे। ट्रेन मेरठ से लखनऊ के बीच 64 किमी प्रति घंटा की औसत रफ्तार चलकर सफर सात घंटा 10 मिनट और लखनऊ से मेरठ के बीच 63.29 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से सात घंटा 15 मिनट में सफर पूरा करेंगे। सोनिया डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि ट्रेन की संचालन और शेड्यूल की सूची प्राप्त हो गई है।

दिल्ली मेट्रो गढ़ रही नए-नए रिकॉर्ड, पर सामने आई चौंकाने वाली बात; रेड, ब्लू और पिंक लाइन पर क्या हुई परेशानी?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ी है। इस वजह से दिल्ली मेट्रो अधिक यात्रियों के सफर के नए-नए रिकॉर्ड गढ़ रही है। इस वजह से पिछले एक वर्ष में मेट्रो में अधिक यात्रियों के सफर के रिकॉर्ड चार बार ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि मेट्रो में यात्रियों की भीड़ बढ़ने के बावजूद तीन कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेनों की संख्या कम हो गई है।

इनमें रेड लाइन (रिताला-समयपुर बादली), ब्लू लाइन (द्वारका सेक्टर 21-इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा/वैशाली) व पिंक लाइन (मजलिस् पार्क-मौजपुर) शामिल है। यह बात जनवरी 2018 से अप्रैल 2024 के बीच दिल्ली मेट्रो के सभी कॉरिडोर पर हर माह चलने वाली औसत ट्रेनों की संख्या के एक डाटा से सामने आया है। इसके मुताबिक, रेड व ब्लू लाइन पर चार व पिंक लाइन पर सात ट्रेनें कम हुई हैं।

वहीं, इस मामले पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी DMRC) की प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ट्रेनें कम होने से मेट्रो की फ्रिक्वेंसी कम होना लाजमी है। ब्लू लाइन दिल्ली मेट्रो का दूसरा सबसे व्यस्त कॉरिडोर है।

वहीं, शुरुआत में इस कॉरिडोर पर 59-61 मेट्रो ट्रेनें का परिचालन होता था। मार्च 2019 में इस कॉरिडोर का नोएडा सिटी सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक विस्तार हुआ। इसके बाद अप्रैल 2019 से ब्लू लाइन पर मेट्रो की संख्या बढ़कर 64 कर दी गई। कोरोना काल को छोड़कर दिसंबर 2021 तक इस कॉरिडोर पर हर माह औसतन 63-64 ट्रेनें चलती थीं। लेकिन दिसंबर 2022 से इस कॉरिडोर पर हर महीने औसतन 60 ट्रेनें का परिचालन हुआ। इस दौरान सिर्फ तीन माह ऐसे रहे जब 61 ट्रेनें चलाई गईं तो कई माह में 58 व 59 ट्रेनें भी चलाई गईं। मार्च 2019 में रेड लाइन का दिलशाद गार्डन से न्यू बस अड्डा गाजियाबाद तक विस्तार हुआ। तब इस कॉरिडोर पर 33-34 ट्रेनें का परिचालन हो रहा है। जून 2023 से इस वर्ष अप्रैल के बीच हर माह प्रतिदिन औसतन 30-31 ट्रेनें का परिचालन हुआ। गत दिसंबर से लगातार 30 ट्रेनें का परिचालन किया गया।



वहीं, फेज तीन में तैयार पिंक लाइन पर मार्च 2018 से अगस्त 2021 के बीच पांच चरणों में मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ। शुरुआत में इस कॉरिडोर पर 14 मेट्रो चल रही थीं। यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ इस कॉरिडोर पर 41 मेट्रो ट्रेनें का परिचालन होने लगा था लेकिन लगातार 13 माह 32-34 ट्रेनें का परिचालन हुआ। यलो लाइन, ग्रीन लाइन, मजेटा लाइन, ग्रेलाइन, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ट्रेनें कम नहीं हुई हैं।

वायलेट लाइन पर 38 ट्रेनें का परिचालन होता था। इस कॉरिडोर पर एक से दो ट्रेनें इस पर भी कम हुई हैं। प्रतिदिन 17 से 18 घंटे मेट्रो का परिचालन होता है। ऐसे में बताया जा रहा है कि एक ट्रेन कम होने से रेड व पिंक लाइन पर मेट्रो के 14 से 15 फेरे व ब्लू लाइन पर 10-11 फेरे कम हो सकते हैं। पहले के मुकाबले ब्लू लाइन व रेड लाइन पर मेट्रो की फ्रिक्वेंसी भी कम हुई है। लेकिन इन दोनों कॉरिडोर पर कोच बढ़ाने का भी दावा किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) का दावा है कि अगस्त 2018 के कार्यालय में तुलना में इस वर्ष अगस्त के कार्यालय में 20 प्रतिशत ट्रेनें का परिचालन अधिक हुआ है। कोच की संख्या भी 26 प्रतिशत बढ़ी है।

वहीं, डीएमआरसी ने माना है कि रेड लाइन पर ट्रेनें की संख्या कम रही है, लेकिन कोच अधिक इस्तेमाल किए गए। किसी कॉरिडोर पर ट्रेनें की संख्या परिचालन व रखरखाव की जरूरतों के अलावा कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। जिसमें त्योहारी सीजन, व्यापार मेला, कार्यालय, सप्ताहांत व यात्रियों के दबाव पर निर्भर करता है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई गई हैं। डीएमआरसी के नेटवर्क में 336 ट्रेनें (2326 कोच हैं), जो वर्तमान ट्रैफिक दबाव को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

मौजूदा कार्यालय में ट्रेनें का परिचालन रेड लाइन: आठ कोच की 32 ट्रेनें (कुल 256 कोच)

ब्लू लाइन: आठ कोच की 66 ट्रेनें (कुल 528 कोच)

पिंक लाइन: छह कोच की 44 ट्रेनें (कुल 264 कोच)

वायलेट लाइन: छह कोच की 40 ट्रेनें (240 कोच)

इन चार कॉरिडोर पर कुल ट्रेनें: 182 ट्रेनें/1288 कोच

भारी बारिश की वजह से ट्रेन सेवाएं रहीं बाधित, मुंबई राजधानी और पश्चिम एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें निरस्त

भारी बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। वडोदरा रेल मंडल में ट्रेक पर पानी भरने से मुंबई से उत्तर भारत आने वाली कई ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। पूर्व दिशा की कई ट्रेनें विलंब से दिल्ली पहुंच रही हैं। इससे दिल्ली और इसके आसपास के शहरों के यात्रियों को परेशानी हो रही है।

देश के कई हिस्से में हो रही मूसलधार वर्षा से ट्रेनें की आवाजाही बुरी तरह से बाधित हो रही है। वर्षा के

कारण वडोदरा रेल मंडल में ट्रेक पर पानी भर गया है जिससे मुंबई से उत्तर भारत आने वाली कई ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। पूर्व दिशा की कई ट्रेनें विलंब से दिल्ली पहुंच रही हैं। इससे दिल्ली और इसके आसपास के शहरों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

29 अगस्त को नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस (12952), दिल्ली सराय रोहिल्ला-बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस (22950) और हरिद्वार-बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस (22918) निरस्त रही। 30 अगस्त को अमृतसर-मुंबई सेंट्रल पश्चिम एक्सप्रेस (12926) नहीं चलेगी।



दिल्ली में ऑटो-रिक्शा वालों की बल्ले-बल्ले, 1.5 लाख वाहनों को ट्रेकिंग शुल्क देने से मिली छूट

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक वाहनों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 1.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहनों को वाहन ट्रेकिंग शुल्क से छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने 2019 में भी ऑटो-रिक्शा के लिए वाहन ट्रेकिंग शुल्क माफ कर दिया था। पढ़िए गहलोत ने और क्या-क्या कहा है?

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने लगभग 1.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहनों को वाहन ट्रेकिंग शुल्क से छूट दे दी है। इस आशय की घोषणा परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में की। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि वर्ष 2019 में सरकार ने ऑटो-रिक्शा के लिए वाहन

ट्रेकिंग शुल्क माफ कर दिया था। दिल्ली में 2.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहन गहलोत ने कहा, रदिल्ली में 2.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहन हैं, जिनमें 85,000 ऑटो-रिक्शा भी शामिल हैं। ऑटो-रिक्शा को पहले से ही 1,200 रुपये वाहन ट्रेकिंग शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। अब, लगभग 1.5 लाख वाहनों को भी इस वार्षिक शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी।

मालूम हो कि वार्षिक वाहन ट्रेकिंग शुल्क 1,200 रुपये है, जो 18 प्रतिशत कर लगाने के बाद लगभग 1,400 रुपये है। दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (डीआईएमटीएस) वर्ष 2019 से



वाहन ट्रेकिंग का प्रभारी रहा है। गहलोत ने कहा, रहमने डीआईएमटीएस के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है और वाहनों को ट्रेक करने के लिए एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

टैपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website: www.tolwa.in
Email: tolwadelhi@gmail.com
bathasanjaybathia@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम-डीएल-0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए-4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉर्पोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बगाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

कंक्रीट की सड़कों का दुष्परिणाम: जल निकासी की समस्या और पर्यावरण की अनदेखी

नई दिल्ली। आजकल शहरी विकास की दौड़ में कंक्रीट की सड़कों का निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है। परंतु, इस निर्माण की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी की जा रही है, जिनके कारण शहरों में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम जल निकासी में आने वाली कठिनाइयों के रूप में देखा जा सकता है।

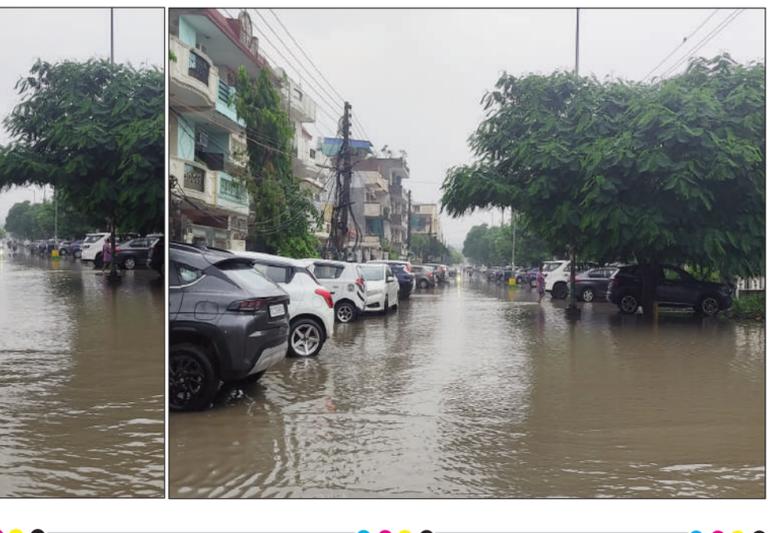
उदाहरण के तौर पर, फरीदाबाद का उल्लेख किया जा सकता है, जहां सड़कों के निर्माण के दौरान लोगों की समझदारी ने नालियों को ही दफन कर दिया। पक्की सड़कों के निर्माण के चक्कर में नालियों को ढक दिया गया, जिससे पानी के बहाव का रास्ता ही बंद हो गया।

इन क्षेत्रों में सड़कों को तो मजबूती से बना दिया गया, परंतु जो थोड़ी बहुत खुली भूमि बची थी, उसे भी कंक्रीट डालकर मजबूती प्रदान कर दी गई। इस प्रक्रिया में न तो पेड़-पौधों के लिए कोई जगह छोड़ी गई

और न ही नालियों के लिए। इसका नतीजा यह हुआ कि थोड़ी सी भी बारिश होने पर पूरे इलाके में जलभराव की स्थिति बन जाती है। महज एक घंटे की बारिश में ही इलाका जलमग्न हो जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

सड़कों के इस बेहतर निर्माण ने वेशक आवागमन को सुगम बनाया है, परंतु इसके दुष्परिणाम अत्यंत चिंताजनक हैं। जल निकासी की समस्या के साथ-साथ पर्यावरण पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

अतः यह आवश्यक है कि शहरी विकास के नाम पर पर्यावरण और जल निकासी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी न की जाए। सड़कों का निर्माण करते समय इन पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि विकास और पर्यावरण संतुलन के बीच सामंजस्य बना रहे। विकास का असली अर्थ तभी है जब वह समग्र और संतुलित हो, न कि केवल एक क्षेत्र में अत्यधिक ध्यान देकर अन्य पहलुओं को उपेक्षा की जाए।



हमें भी अपने जीवन में माँ पार्वती के आदर्शों को धारण करना चाहिए

माँ पार्वती ने जो सूखे पत्ते खाकर उपवास रखे हुए थे, अब उन्होंने वे भी छोड़ दिए। अब वे कुछ भी ग्रहण नहीं करती थीं। सूखे पत्ते छोड़ने पर ही उनका नाम 'अपर्णा' पड़ा। माँ पार्वती जी का इतना भयंकर तप देख कर आकाशवाणी हुई, कि हे पर्वतराज की सुपुत्री! सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ।

श्रीपार्वती जी साक्षात् भवानी हैं। वे जगत जननी हैं। लेकिन तब भी वे अपने जीवन चरित्र के माध्यम से यह शिक्षा देना चाहती हैं, कि जीवन में आप अगर महाशक्तिशाली भी हैं, सब प्रकार से संपन्न हैं, तो भी तप का महत्व आप कम नहीं आँक सकते हैं। वर्तमान संसार में आप देखिए, जीव को तनिक सी भी मायावी सफलता प्राप्त हो जाये, वह इतना आलसी हो जाता है, कि प्रत्येक कार्य मशीनों पर ही टाल कर चलता है। तप की तो इसे जैसे आवश्यकता ही नहीं है। जिसका परिणाम यह है, कि व्यक्ति अनेकों भयंकर रोगों से ग्रसित हो चुका है। मन पर कोई अंकुश ही नहीं है। विषय विकारों में ऐसा गलतान हो चुका है, कि मन भयंकर राक्षस हो चुका है। किसी में सहने की शक्ति नहीं बची है। जिस कारण परिवारों में विछेद हो रहे हैं। दया धर्म तो मानों बहुत दूर की कौड़ी हो रकी है। जबकि गोस्वामी जी इतना स्पष्ट कह रहे हैं, कि तप की आवश्यकता तो त्रिदेवों को भी है। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संतार तभी हो पाता है, जब त्रिदेव तप का आसरा लेते हैं—

'तपबल रचइ प्रपंचु बिधाता।



तपबल बिष्नु सकल जग त्रता।।
तपबल संभु करहि संधारा।
तपबल सेषु धरइ महिभारा।।'

इसी तप की महिमा को महिमा मंडित करने के लिए, माँ पार्वती जी तप के निकल पड़ीं।

वे सबसे पहले, कुछ काल तक तो केवल जल और वायु का ही सेवन करती हैं। फिर अनेकों प्रकार के कठोर उपवास करती हैं। उसके पश्चात्, जो बेल पत्र सूख कर धरती पर गिर जाते थे, माँ पार्वती ने उन्हें बेल पत्रों को ही खाती हैं। वह भी कोई दो चार दिन नहीं, अपितु पूरे तीन हजार वर्ष—

'कछु दिन भोजनु बारि बतासा।
किए कठिन कछु दिन उपवासा।।
बेल पाती महि परइ सुखाई।।'

तीन सहस्र संबत सोइ खाई।।'
माँ पार्वती ने जो सूखे पत्ते खाकर उपवास रखे हुए थे, अब उन्होंने वे भी

छोड़ दिए। अब वे कुछ भी ग्रहण नहीं करती थीं। सूखे पत्ते छोड़ने पर ही उनका नाम 'अपर्णा' पड़ा। माँ पार्वती जी का इतना भयंकर तप देख कर आकाशवाणी हुई, कि हे पर्वतराज की सुपुत्री! सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कष्टों को छोड़ कर अपनी सामान्य अवस्था को प्राप्त हो। अब महान कष्टों की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम भगवान शंकर से मिलने के लिए सिद्ध हो चुकी हो। ब्रह्मा जी द्वारा हुई आकाशवाणी में अत्यंत प्रसन्नता थी। ब्रह्मा जी कहा रहे थे, कि हे भवानी! संसार में बहुत से धीर, मुनि और ज्ञानी हुए हैं। किंतु ऐसा कठोर तप आज तक किसी ने भी नहीं किया। अब मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूँ, उसे श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी समझकर अपने हृदय में धारण करना। हे भवानी! अब आपके पिता जी आपको बुलाने आयेगे। तब ऐसा न हो,

कि आप तप ही करते रहियेगा। आप उनका कहना मान कर एवं हठ छोड़ कर उनके साथ घर चले जाना। केवल इतना ही नहीं, जब तुम्हें सपत्ति मिले, तब इस वाणी को ठीक मानना।

माँ पार्वती ने जैसे ही यह आकाशवाणी सुनी, तो उनकी प्रसन्नता की कोई पार न रही। हर्ष के मारे उनका सरीर पुलकित हो गया। उन्होंने अपने जीवन के सार को पाने के लिए लक्ष्य को भेद दिया।

आवश्यकता है कि हम भी अपने जीवन में माँ पार्वती के आदर्शों को धारण करें। ठीक है, हम अपने जीवन में अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। किंतु यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए, कि हमारा प्रथम कार्य व लक्ष्य ईश्वर को पाना है। उसमें ही विलीन हो जाना है।

पिंपल्स का सफाया कर सकते हैं ये घरेलू नुस्खे, आप भी आजमाकर देखें



आप नेचुरल तरीके से भी कुछ सस्ते और असरदार तरीके अपनाकर फेस को पिंपल्स फ्री बना सकती हैं। इसलिए आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में बताने जा रहे हैं।

फेस पर पिंपल्स होना एक नेचुरल बात होती है, लेकिन समस्या तब होती है जब फेस पर पिंपल्स बढ़ने लगते हैं। वहीं कई बार पिंपल्स फेस पर दाग छोड़ जाते हैं। इन दागों से निजात पाने के लिए हम सभी तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं। ऐसे में आप नेचुरल तरीके से भी कुछ सस्ते और असरदार तरीके अपनाकर फेस को पिंपल्स फ्री बना सकती हैं। इसलिए आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में बताने जा

रहे हैं, जिनको अपनाकर आप अपनी त्वचा को पिंपल्स फ्री बना सकती हैं।

शहद है फायदेमंद
फेस से पिंपल्स को दूर करने के लिए आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। शहद एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। इसलिए इसके कई फायदे होते हैं। आप फेस पर पिंपल्स निकलते ही इसके ऊपर शहद को एक-दो बूंद लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। फिर अगले दिन सुबह ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। ऐसा करने से पिंपल्स नहीं होंगे।

बर्फ का करें इस्तेमाल
फेस पर बर्फ की सिकाई करने से पिंपल्स के सूजन और दर्द से राहत मिलती है। बर्फ को एक टिश्यू में लें और फिर इसको चेहरे के जिस एरिया पर अधिक पिंपल्स होते हैं, वहां पर थपकी देते हुए सिकाई करें। इससे फेस पर बैक्टीरिया

कम होते हैं और चेहरा एक्ने फ्री होता है।

एलोवेरा है फायदेमंद
बता दें कि एलोवेरा का छिलका और उसका गूदा दोनों ही पिंपल्स में काफी फायदेमंद साबित होता है। एलोवेरा के पल्प को नीम के पाउडर में मिक्स कर फेस पर अप्लाई करें। फेस के जिस हिस्से पर कील-मुंहासे ज्यादा होते हैं, आप वहां पर एलोवेरा के छिलके को रगड़कर पिंपल्स फ्री बना सकते हैं।

ग्रीन टी का करें इस्तेमाल
स्किन के लिए ग्रीन टी काफी फायदेमंद होती है। आप गर्म पानी में इसको उबाल लें और फिर इस पानी को ठंडा कर फेस पर स्प्रे करें। इस उपाय को करने से पिंपल्स की समस्या कम होती है और आपकी त्वचा भी बैक्टीरिया फ्री रहती है। ग्रीन टी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पिंपल्स के दाग नहीं पड़ने देते हैं।

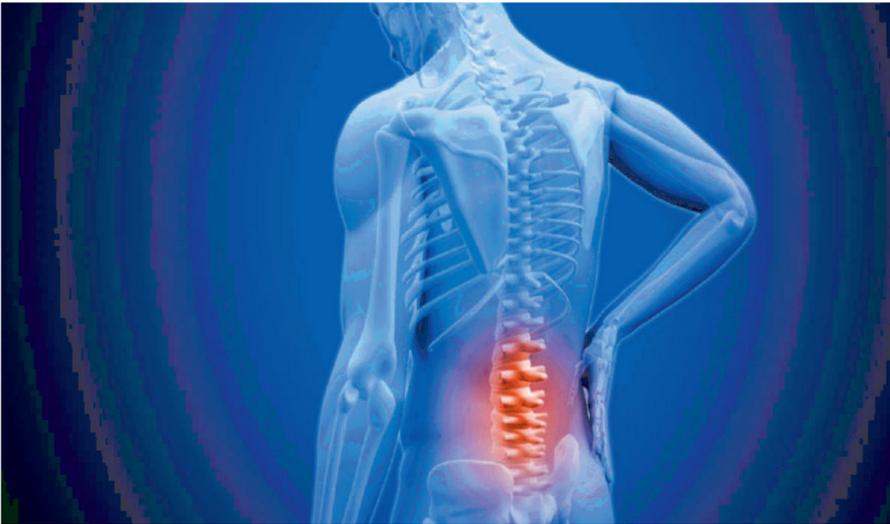
50 की उम्र में भी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए करें ये उपाय, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

लाइफस्टाइल में गड़बड़ी और आहार की गड़बड़ी ने इन खतरों को बढ़ा दिया है। हड्डियों की मजबूती बनी रहें, इसके लिए कम उम्र से ही प्रयास किया जाना चाहिए। हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए पौष्टिकता से भरपूर डाइट लेनी चाहिए।

उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों की कमजोरी और हड्डी संबंधित विकारों का खतरा बढ़ने लगता है। आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं की वजह से लोगों का उठना-चलना भी मुश्किल हो जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट की मानें, तो लाइफस्टाइल में गड़बड़ी और आहार की गड़बड़ी ने इन खतरों को बढ़ा दिया है। हड्डियों की मजबूती बनी रहें, इसके लिए कम उम्र से ही प्रयास किया जाना चाहिए। आहार में कैल्शियम और विटामिन डी जैसे पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को शामिल करना चाहिए। रोजाना नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। जिससे हड्डियों के जोखिम को कम किया जा सके।

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें, हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए पौष्टिकता से भरपूर डाइट लेनी चाहिए। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन उपायों से आप 50 की उम्र में भी हड्डियों की मजबूती बनाए रख सकते हैं और इन उपायों से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं का खतरा भी कम होगा।

जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
बता दें कि 30 साल से कम उम्र के लोगों में भी पीठ और कमर दर्द की शिकायत देखने को मिल रही है। वहीं समय से पहले ही जोड़ों व गठिया की समस्या बढ़ रही है। इसका मुख्य



कारण लंबे समय तक बैठना, लाइफस्टाइल में गड़बड़ी, फिजिकल एक्टिविटी न करना आदि है। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए कम उम्र से ही प्रयास करना बेहद जरूरी है। यदि आप शुरूआत से ही तीन बातों का ध्यान रखते हैं, तो 50 की उम्र में भी आपकी हड्डियों की मजबूती बनी रह सकती है।

शारीरिक निष्क्रियता
फिजिकल एक्टिविटी का कम होना और ज्यादा देर तक बैठे रहने की आदत क्रोनिक बीमारियों को बढ़ावा देती है। जिसके कारण हड्डियों संबंधित समस्या होने का भी खतरा बना रह सकता है। हमारे जोड़ों को चिकनाई और हेल्दी रहने के लिए गतिशीलता की जरूरत होती है। वहीं लंबे समय तक बैठे रहने से जोड़ों

में अकड़न हो जाती है। जिससे गठिया जैसी बीमारियों का खतरा रहता है। इसलिए लंबे समय तक बैठे रहने से बचें और रोजाना एक्सरसाइज या योग आदि कर आप हड्डियों की समस्या से बच सकते हैं।

पौष्टिक आहार
पौष्टिक आहार हड्डियों से लेकर शरीर के सभी अंगों के लिए लाभकारी माना जाता है। हड्डियों के लिए कैल्शियम से बेहतर कुछ नहीं होता है। आपको डेयरी उत्पादों का सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो कम करने में मदद करता है। अपनी डाइट में विटामिन डी और नट्स वाली चीजों का भी सेवन करें। क्योंकि विटामिन डी के बिना

कैल्शियम का अवशोषण नहीं होता है। ऐसे में कम उम्र से ही पौष्टिक आहार का सेवन कर आप हड्डियों की समस्या से बच सकते हैं।

धूम्रपान से बचना
बता दें कि सिगरेट में मौजूद निकोटीन हड्डियों को बनाने वाले ऑस्टियोब्लास्ट के उत्पादन को धीमा कर देता है। इससे हड्डियों का नेचुरल रूप से क्षरण होता है और नई हड्डियां नहीं बन पाती हैं। धूम्रपान करने से डाइट में कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, तो धूम्रपान की आदत से तौबा करना चाहिए। धूम्रपान करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या देखी जाती है।

मूलकर भी न करें रसोईघर से जुड़ी ये गलतियां, वरना नाराज हो सकती हैं मां अन्नपूर्णा



हिंदू धर्म के मुताबिक रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। मां अन्नपूर्णा को अनाज और भोजन की देवी मानी जाती है। इसलिए रसोई हमारे घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।

हिंदू धर्म के मुताबिक रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। मां अन्नपूर्णा को अनाज और भोजन की देवी मानी जाती है। इसलिए रसोई हमारे घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। लेकिन रसोई घर से संबंधित कुछ नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए। इन नियमों का ध्यान न

रखने से मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि मां अन्नपूर्णा की कृपा बनाए रखने के लिए किन गलतियों को करने से बचना चाहिए।

न करें ये गलतियां
बता दें कि रसोई घर की साफ-सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी सिर्फ साफ-सुथरे स्थानों पर निवास करती हैं। साथ ही कभी भी जूते-चप्पल पहनकर रसोई में नहीं जाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। रसोई में स्नान करने के बाद ही जानना चाहिए, इससे मां अन्नपूर्णा की आप पर कृपा बनी रहती है।

इन बातों का भी रखें ख्याल

रोजाना रात में खाना खाने के बाद कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और व्यक्ति पर संकटों का पहाड़ टूट सकता है। इसलिए हमेशा बर्तनों को साफ करने के बाद ही सोना चाहिए। वहीं यदि आपकी रसोई में नल टपक रहा है, तो उसको फौरन ठीक करवा लेना चाहिए। वरना इससे आपके खर्च बढ़ सकते हैं।

बढ़ने लगते हैं लड़ाई-झगड़े
कुछ लोगों की आदत होती है कि वह खाना बनाने के दौरान उसको टेस्ट कर देखते हैं। लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, तो ऐसा करना सही नहीं माना जाता है। इसके अलावा कभी भी रसोई र में बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। इससे परिवार में लड़ाई-झगड़े बढ़ने लगते हैं।

श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती है अयोध्या नगरी

राम जन्मभूमि अयोध्या का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है। यह वह स्थान है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। यहाँ पर स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और यह स्थल हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है।

अयोध्या, उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन और धार्मिक शहर है जो भारतीय संस्कृति और इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। यह नगर भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अयोध्या की यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का अनुभव कराती है, बल्कि इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का अन्वेषण भी करती है। आइए जानें अयोध्या के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में:

1. राम जन्मभूमि
राम जन्मभूमि अयोध्या का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है। यह वह स्थान है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। यहाँ पर स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और यह स्थल हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। मंदिर परिसर में भगवान राम

की आराधना और पूजा का अनुभव एक दिव्य और आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है।

2. हनुमान गढ़ी
हनुमान गढ़ी, अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और अयोध्या के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यहाँ पर एक भव्य मूर्ति है और इसे भगवान राम के भक्तों के लिए एक विशेष स्थल माना जाता है। मंदिर की शांति और भक्तिमय वातावरण एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं।

3. कनक भवन
कनक भवन, भगवान राम और सीता के जीवन की एक महत्वपूर्ण झलक प्रस्तुत करता है। यह मंदिर विशेष रूप से सुंदर और भव्य है और इसे राजा दशरथ द्वारा निर्मित करवाया गया था। मंदिर की वास्तुकला और यहाँ पर स्थापित भगवान राम और सीता की मूर्तियाँ दर्शनीय हैं।

4. श्री दुर्गा जी का मन्दिर
श्री दुर्गा जी का मन्दिर अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और यहाँ पर नियमित पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर का शांतिपूर्ण वातावरण और धार्मिक महत्व श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है।

5. श्री राम की पैड़ी
श्री राम की पैड़ी, अयोध्या का एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पर श्रद्धालु गंगा नदी के समान निर्मित सरोवर में स्नान करते हैं। यहाँ की धार्मिक मान्यता और धार्मिक क्रियाएँ इस स्थान को विशेष बनाती हैं।

6. साक्षी गोपाल मंदिर
साक्षी गोपाल मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में शामिल है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति और मंदिर का शांत वातावरण भक्तों के लिए एक दिव्य अनुभव प्रदान करता है।

7. नंदनी वन
नंदनी वन, अयोध्या के प्राचीन वन क्षेत्रों में से एक है। यह स्थल भगवान राम के वनवास के दौरान की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर वन्य जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया जा सकता है।

8. स्वर्गद्वारी आश्रम
स्वर्गद्वारी आश्रम, अयोध्या का एक प्रमुख आश्रम है जहाँ पर योग और ध्यान की विधियाँ सिखाई जाती हैं। यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण और साधना की विधियाँ आध्यात्मिक उन्नति के लिए आदर्श हैं।



9. शबरी आश्रम
शबरी आश्रम, भगवान राम के वनवास के दौरान शबरी माता के द्वारा बनाए गए आश्रम का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर शबरी माता की पूजा अर्चना की जाती है और यह स्थल धार्मिक मान्यता

से भरपूर है।
निष्कर्ष
अयोध्या, धार्मिकता, संस्कृति और इतिहास का एक अनूठा संगम है। यहाँ की धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहर और आध्यात्मिक वातावरण

आपकी यात्रा को एक अविस्मरणीय अनुभव बनाएंगे। चाहे आप धार्मिक आस्था के लिए आएँ या भारतीय संस्कृति का गहरा अनुभव करना चाहें, अयोध्या आपके लिए एक आदर्श गंतव्य साबित होगा।

संसद भवन की सुरक्षा में फिर सेंध, नकली पास की मदद से घुसने की कोशिश कर रहे युवक को मुस्तैद सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ा

परिवहन विशेष

संसद भवन की सुरक्षा में एक और बड़ी चूक सामने आई है। बुधवार सुबह 10 बजे सीआईएसएफ कर्मियों ने संसद के प्रवेश द्वार पर चेकिंग के दौरान एक दिहाड़ी मजदूर को जाली पास के साथ पकड़ा। इस घटना ने संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस मामले की जांच संसद मार्ग थाना कर रहा है।

नई दिल्ली। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध का एक और मामला सामने आया है। मामला बुधवार सुबह 10 बजे का है। सीआईएसएफ कर्मियों ने संसद के प्रवेश द्वार पर चेकिंग के दौरान जाली पास के साथ एक दिहाड़ी मजदूर को पकड़ लिया। उसके पास मिले पास के बारे में पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह पास उसे कंप्यूटर ऑपरेटर तुषार यादव ने मुहैया कराया था।

तुषार यादव से पूछताछ करने पर उसने गलती स्वीकार की और माफी मांगी। इसपर आगे की जांच के लिए मजदूर को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। संसद मार्ग थाना

इस मामले में जांच कर रहा है।

16 अगस्त को भी एक युवक दीवार फांदकर संसद में घुसा

बीते 16 अगस्त को भी एक युवक दीवार फांदकर संसद परिसर में घुस गया था। वहां तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने युवक को पकड़ लिया था। घटना की जानकारी मिलते ही सभी सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई थी। संसद भवन में आईबी समेत अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने उससे घंटों पूछताछ करने के उसे संसद मार्ग पुलिस को सौंप दिया था। वह इन्फियाज खान रोड की तरफ से संसद भवन की दीवार फांदकर अंदर घुस आया था। युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी मनीष के रूप में हुई थी। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी।

बीते साल 13 दिसंबर को चार युवकों ने लगाया था सेंध

संसद भवन की सुरक्षा में चूक का यह कोई नया मामला नहीं है। 2001 में संसद पर हमले की बरसी पर पिछले साल 13 दिसंबर को संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान चार व्यक्तियों ने प्रवेश किया था। वे लोग मुख्य



हाल से कूदकर लोकसभा में दाखिल हुए थे। इन्होंने यहां पीले रंगा धुआं छोड़ा था और उसी समय संसद के बाहर भी दो लोगों ने नारेबाजी की थी। हालांकि सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में ही हैं।

सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंपा गई

इस घटना के बाद संसद की आंतरिक

सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ से लेकर सीआईएसएफ को सौंप दी गई थी। इसी साल चार जून को संसद भवन प्लैप गेट पर पास चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ कर्मियों ने कासिम, मोनिस और शोएब नामक तीन व्यक्तियों को पकड़ा था जो फर्जी आधार दिखाकर संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बाद में पूछताछ के बाद इन्हें छोड़ दिया गया था।

नियमों का पालन नहीं करने पर एअर इंडिया एक्सप्रेस पर डीजीसीए ने लगाया 10 लाख का जुर्माना



परिवहन विशेष

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नियमों का पालन नहीं करने के कारण एअर इंडिया एक्सप्रेस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने जून में किए गए निरीक्षण में पाया कि एअर इंडिया एक्सप्रेस ने उड़ान रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को मुआवजा संबंधी नियमों का पालन नहीं किया। एअर इंडिया एक्सप्रेस को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने

नियमों का पालन नहीं करने के लिए एअर इंडिया एक्सप्रेस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने जून में किए गए निरीक्षण में एअर इंडिया एक्सप्रेस को नियमों का अनुपालन नहीं करते हुए पाया। नियमों का अनुपालन न करने के लिए एअर इंडिया एक्सप्रेस को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।

एअर इंडिया एक्सप्रेस के जवाब से पता चला कि एयरलाइन ने उड़ान रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को मुआवजा संबंधी नियमों का पालन नहीं किया। वहीं डीजीसीए ने उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) के रूप में काम करने

के लिए अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को दी गई मंजूरी को निर्रिवत कर दिया।

विमान दुर्घटना के बाद की गई कार्रवाई

एक प्रशिक्षण विमान के 20 अगस्त को दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यह कार्रवाई की गई। इस दुर्घटना में विमान में सवार दोनों व्यक्तियों यानी प्रशिक्षण पायलट और प्रशिक्षक की जान चली गई थी। दुर्घटना के बाद डीजीसीए ने 23 और 24 अगस्त को 'अल्केमिस्ट एविएशन' का विशेष सुरक्षा ऑडिट किया। डीजीसीए ने गुरुवार को बताया, ऑडिट के दौरान कई गंभीर कमियां मिलीं।

'दिल्ली में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 होगी', विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की घोषणा

परिवहन विशेष

कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने हिमाचल प्रदेश सरकार के बाल विवाह निषेध विधेयक की सराहना की और कहा कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वे भी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सड़कें टूटी हैं पीने का पानी गंदा आता है जरा सी वर्षा में जगह जगह जलभराव हो जाता है।

नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के बाल विवाह निषेध विधेयक की सराहना की और वादा किया कि अगर राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो वह भी इसी तरह का कदम उठाएगी। मालूम हो कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने लड़कियों के



लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। यादव पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के 'आप का विधायक, आपके द्वार' अभियान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जनता सवाल पूछ रही, 10 साल में दिल्ली बदहाल, कहाँ थे विधायक और कहाँ थी सरकार? **चुनाव का समय आया तो विधायकों को जनता याद**

आई. देवेंद्र उन्होंने कहा कि राजधानी में सड़कें टूटी हैं, पीने का पानी गंदा आता है, जरा सी वर्षा में जगह जगह जलभराव हो जाता है, प्रदूषण और जाम यहां की स्थायी समस्या बन गया है। अब चुनाव का समय आया तो विधायकों का जनता याद आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन और पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज और पूर्व विधायक कुंवर करण सिंह भी मौजूद थे।

दिल्लीवासियों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएगी 'कृत्रिम वर्षा', विंटर एक्शन प्लान को लेकर सामने आई सरकार की योजना

परिवहन विशेष

दिल्ली सरकार सर्वियों के प्रदूषण से निपटने के लिए 14 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान बना रही है। विशेषज्ञों के सुझाव पर गंभीर श्रेणी के प्रदूषण वाले दिनों में कृत्रिम वर्षा कराने पर विचार किया जा रहा है। अन्य सुझावों में जागरूकता अभियान चलाना पहले से ही वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करना ऑड इवेन की जगह एक स्टाट की गाड़ियों पर स्वेच्छक प्रतिबंध का फार्मूला लागू करना शामिल है।

नई दिल्ली। सर्वियों के प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार 14 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान बनाएगी। इसी प्लान पर विशेषज्ञों के साथ राय सलाह मशविरा करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को सचिवालय में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी। इसमें डीपीसीसी, पर्यावरण विभाग, यूएनईपी, एपिक इंडिया, क्लिन एयर एशिया, आईआईटी कानपुर सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए।

इस बैठक के बाद प्रेस वार्ता में गोपाल राय ने बताया कि विशेषज्ञों ने 'गंभीर' श्रेणी के प्रदूषण वाले दिनों में दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने का सुझाव दिया। इस सुझाव पर आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों और सभी



संबंधित विभागों के साथ बैठक करने के लिए वह शुरुवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखेंगे।

पांच सितंबर को विभागों के साथ होगी समीक्षा बैठक

राय ने कहा कि 78 विभागों और संस्थाओं के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के सुझावों पर आगे का विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इस बैठक का उद्देश्य भी यही था कि विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझाव से विंटर एक्शन प्लान को और प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि पांच सितंबर को सभी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर संयुक्त कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

हॉटस्पॉट के लिए अलग-अलग कार्य योजना

गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर हॉटस्पॉट के लिए अलग-अलग कार्य योजना बनाई जाएगी। विशेषज्ञों ने भी राय दी है कि इन सभी हॉट स्पॉट पर अलग-अलग एक्शन प्लान बनाकर वहां के प्रदूषण को घटाया जाए, जिससे दिल्ली में प्रदूषण को और कम किया जा सके।

विशेषज्ञों से मिले कई तरह के सुझाव

उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों से मिले अन्य सुझावों में प्रदूषण से संबंधित लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना, जागरूकता अभियान

चलाना, पहले से ही वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करना, ऑड इवेन की जगह एक स्टाट की गाड़ियों पर स्वेच्छक प्रतिबंध का फार्मूला लागू करना, विभिन्न ऑफिस की टाइमिंग को अलग-अलग करने का सुझाव, सर्वियों में बायोमास बर्निंग को रोकने के लिए सोसायटी के गाड़ों को हीटर वितरित करने का सुझाव, हाट स्पॉट पर इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने जैसे सुझाव शामिल रहे। मंत्री ने कहा कि इन सभी सुझावों को विंटर एक्शन प्लान में शामिल किया जाएगा।

- ये हैं 14 सूत्रीय फोकस बिंदु**
- 1- धूल प्रदूषण
 - 2- वाहनों से होने वाले प्रदूषण
 - 3- पराली जलाना
 - 4- ओपन कूड़ा बर्निंग
 - 5- औद्योगिक प्रदूषण
 - 6- ग्रीन वार रूम एवं ग्रीन ऐप
 - 7- हॉट स्पॉट
 - 8- रियल टाइम सोर्स अपाशंमेंट स्टडी
 - 9- हरित क्षेत्र को बढ़ाना / वृक्षारोपण
 - 10- ई-वेस्ट इको पार्क
 - 11- जन भागीदारी को बढ़ावा
 - 12- उपायों पर प्रतिबंध
 - 13- केंद्र सरकार एवं पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद
 - 14- ग्रेप का प्रभावी क्रियाचरण

सोमवती अमावस्या पर दिल्ली के लोगों को नहीं होगी परेशानी, हरिद्वार से सीधे शाहदरा के चलेगी विशेष ट्रेन

परिवहन विशेष

सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने हरिद्वार से दिल्ली के शाहदरा तक एक विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 2 सितंबर को हरिद्वार से शाम 4:45 बजे रवाना होगी और रात 10:30 बजे शाहदरा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। रास्ते में इसका ठहराव रुड़की तपरी मुजाफरनगर मेरठ सिटी और गाजियाबाद में होगा।

नई दिल्ली। सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने हरिद्वार से दिल्ली के शाहदरा तक विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि सोमवती



अमावस्या पर बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाते हैं। इसे ध्यान में रखकर दो सितंबर को हरिद्वार से दिल्ली शाहदरा के लिए विशेष अनारक्षित ट्रेन चलेगी। यह विशेष ट्रेन हरिद्वार से शाम पांच बजे रवाना होगी और रात 10:30 बजे शाहदरा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। रास्ते में इसका ठहराव रुड़की, तपरी, मुजाफरनगर, मेरठ सिटी और गाजियाबाद में होगा। हरिद्वार से शाम 5:20 बजे बटिंडा

के लिए भी एक विशेष अनारक्षित ट्रेन चलेगी। **हाल ही में वैष्णो देवी के लिए तीन ट्रेनों का परिचालन शुरू** बता दें, उत्तर रेलवे ने हाल ही में दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा के लिए तीन स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया था। तीनों ट्रेनों का सोनीपत में ठहराव दिए जाने से उत्तर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तरफ जाने यात्रियों को राहत मिलेगी।

दिल्ली के सार्वजनिक शौचालयों की गंभीर स्थिति, तत्काल सुधार की आवश्यकता - मनोज कुमार जैन

परिवहन विशेष। सुष्मा राणी।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के नामित सदस्य, मनोज कुमार जैन, ने दिल्ली के सार्वजनिक शौचालयों की बदतर स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। एमसीडी के आयुक्त श्री अश्वनी कुमार को लिखे गए पत्र में, उन्होंने इन शौचालयों के रखरखाव और विशेष रूप से महिलाओं के लिए अतिरिक्त स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यकता पर बल दिया है।

मुख्य समस्याएँ: अत्यधिक अस्वच्छ स्थिति: दिल्ली के कई सार्वजनिक शौचालयों में जाम की समस्या है, जिसके कारण मूत्र का बाहर बहना और अस्वच्छता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। नियमित सफाई के अभाव में लोग अस्वास्थ्यकर विकल्पों का सहारा लेने पर मजबूर हैं। - बुनियादी सुविधाओं की कमी: कई

सार्वजनिक शौचालयों में हाथ धोने की सुविधा और ठीक से काम करने वाले फ्लश सिस्टम का अभाव है। ढांचे में खराबी और टूटे-फूटे फिटिंग्स आम बात हो गई हैं।

- प्रकाश और वेंटिलेशन की कमी: इन शौचालयों में पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन की अनुपस्थिति विशेषकर रात के समय में एक बड़ी समस्या बन गई है, जिससे इनका उपयोग मुश्किल और असुरक्षित हो जाता है। कीटाणुनाशकों की कमी: नियमित कीटाणुनाशन न होने के कारण, इन शौचालयों से बढ़ते आती हैं, जिससे वातावरण अस्वस्थ और असुविधाजनक हो जाता है। - स्वास्थ्य जोखिम: इन शौचालयों की उपेक्षित स्थिति के कारण ये मच्छरों और अन्य कीटों के प्रजनन स्थल बन गए हैं, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों

का प्रसार हो रहा है, विशेष रूप से आसपास के क्षेत्रों में

महिलाओं के लिए स्वच्छता सुविधाओं की कमी: मनोज कुमार जैन ने पत्र में दिल्ली में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों की गंभीर कमी की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। वर्तमान सुविधाएँ पर्याप्त नहीं हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं।

प्रस्तावित समाधान: इन समस्याओं के समाधान के लिए, मनोज कुमार जैन ने सुझाव दिया है कि स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और ट्रेड्स एं एसोसिएशन को इन शौचालयों के रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाए। इन समूहों को आवश्यक धनराशि प्रदान करें और उन्हें विज्ञापन और हॉर्डिंग के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने की अनुमति



देकर, सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव को काफी हद तक सुधारा जा सकता है।

इसके अलावा, दिल्ली में महिलाओं के लिए अधिक संख्या में सुरक्षित और साफ-सुथरे शौचालयों का निर्माण करना स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने और सभी नागरिकों की गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

AAP पार्षदों ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, चुनाव को लेकर क्यों की ये बड़ी मांग?

परिवहन विशेष

MCD की वार्ड कमेटीयों के चुनाव को लेकर जारी अधिसूचना के खिलाफ आप के पार्षदों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। आप पार्षदों ने चुनाव करने संबंधी 28 अगस्त के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि एमसीडी समेत अन्य प्रतिवादियों को नए सिरे से चुनावों की तारीख घोषित करने को कहा जाए ताकि नामांकन दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की वार्ड कमेटीयों का चुनाव को लेकर जारी अधिसूचना के विरुद्ध आम आदमी पार्टी (आप) पार्षदों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

गुरुवार को वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति

तुषार राव गडेला की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। उन्होंने मामले में तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया। इस पर पीठ ने मामले को 30 अगस्त के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। मामले पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ सुनवाई करेगी।

नामांकन के लिए मिलना चाहिए पर्याप्त समय याचिकाकर्ता डावरी से आप पार्षद तिलोत्तमा चौधरी और दक्षिणपुरी के पार्षद प्रेम चौहान ने याचिका दायर कर नए सिरे से चुनावों की घोषणा की मांग की है। पार्षदों ने चुनाव कराने संबंधी 28 अगस्त के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि एमसीडी समेत अन्य प्रतिवादियों को नए सिरे से चुनावों की तारीख की घोषित करने को कहा, ताकि नामांकन दाखिल करने के लिए सभी को पर्याप्त समय मिल सके।

याचिका में कहा कि प्रत्येक प्रत्याशियों को नामांकन

दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है। याचिका में कहा गया है कि नामांकन दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिए जाने के कारण उम्मीदवार उचित प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकेंगे।

याचिका में यह भी कहा कि आप पार्षद प्रेम चौहान बीमार हैं और ऐसे में कम समय दिए जाने से वह इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को नए सिरे से घोषित किया जाए।

चार सितंबर को होगा चुनाव वहीं, याचिकाकर्ता तिलोत्तमा चौधरी ने कहा कि वह शहर से बाहर हैं और अगर चुनाव हुआ तो वह इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एमसीडी ने 28 अगस्त को वार्ड कमेटीयों के चुनावों की घोषणा की थी। इसके तहत 30 अगस्त तक नामांकन किए जाने हैं और चार सितंबर को इस पर चुनाव होगा।



पाकिस्तान को चटाई थी धूल, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस; कौन थे एयर मार्शल डेंजिल कीलर ?

परिवहन विशेष न्यूज

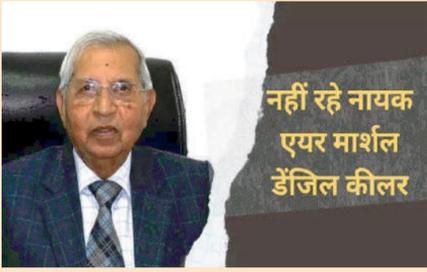
1965 के योद्धा नायक एयर मार्शल डेंजिल कीलर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 90 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। डेंजिल कीलर ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई और वीर चक्र दिया गया था। वे लंबे समय से गुरुग्राम के पालम विहार में रहते थे। पढ़िए उनके बारे में सब कुछ।

गुरुग्राम। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले वीर चक्र विजेता एयर मार्शल (रिट.) डेंजिल जोसेफ कीलर का बुधवार शाम निधन हो गया। वह 90 साल के थे। उनका जन्म 1933 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था।

वह लंबे समय से परिवार सहित गुरुग्राम के पालम विहार इलाके में रह रहे थे। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार दोपहर तीन बजे दिल्ली कैट के शमशान स्थल पर सैनिक सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम संस्कार से पहले कर्नाट प्लेस स्थित चर्च में सुबह 11 बजे से प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी।

डेंजिल जोसेफ कीलर के छोटे भाई ट्रेवर कीलर भी एयर फोर्स में थे। उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ 1965 की लड़ाई में विशेष भूमिका निभाई थी। उस समय दोनों की पहचान एयर फोर्स में लड़ाकू पायलट भाइयों के रूप में थी।

डेंजिल जोसेफ कीलर छह नवंबर 1954 को एयर फोर्स में शामिल हुए थे। उन्होंने 1965 एवं 1971 की



नहीं रहे नायक
एयर मार्शल
डेंजिल कीलर

लड़ाई में खासकर 1965 की लड़ाई में नायक जैसी भूमिका निभाई थी। वह फाइटर पायलट की भूमिका में थे। उन्होंने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी लड़ाकू विमान सेवर जेट को मार गिराया था। इससे पाकिस्तान की हालत काफी पतली हो गई थी। कुछ ही दिनों की लड़ाई में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे।

घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे डेंजिल जोसेफ

डेंजिल जोसेफ कीलर ने 1971 की लड़ाई में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। जीत के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। उस समय वह ग्रुप कैप्टन थे। बताया जाता है कि मार्च 1978 में कीलर काफी ऊंचाई पर टाइप 77 विमान उड़ा रहे थे। उसी दौरान छतरी उड़ गई थी। उस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

उनके लिए विमान को संभालना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था लेकिन वह सफलतापूर्वक विमान को वापस बेस पर ले आए थे। उनकी आंखों में भी काफी दिक्कत आ गई थी। इसके अलावा भी कई बार उन्होंने विमान की आपातकालीन लैंडिंग सफलतापूर्वक बेस पर कराई थी। उनकी पहचान एक कुशल पायलट के रूप में भी थी।

पाकिस्तानी फौज ने बंदी बनाने का किया था प्रयास डेंजिल जोसेफ कीलर के पोते करण कीलर कहते हैं कि उनके दादाजी हमेशा 1965 एवं 1971 की लड़ाई की चर्चा किया करते थे। वह कहते थे कि पूरी दुनिया में भारतीय सेना से अनुशासित सेना कहीं नहीं। रेजांग-ला युद्ध स्मारक के संयोजक मेजर (डा.) टीवी राव कहते हैं कि 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानियों ने डेंजिल जोसेफ कीलर के विमान को शूट कर दिया था। पाकिस्तानी फौज ने बंदी बनाने का प्रयास किया था। उससे पहले ही सात कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडोजन ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया था।

वह इतने जांबाज थे कि कुछ ही दिनों बाद फिर से एयर फोर्स में अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गए थे। सेवानिवृत्ति के बाद वह रेजांग-ला युद्ध स्मारक के अधिकतर समारोह में बड़-चढ़कर भाग लेते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों में जोश भर जाता था। जब तक वह एयर फोर्स में रहे उनके नाम से पाकिस्तानी फौज के होश उड़े रहे।

आठ हजार लोगों से 88 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी! BJP के सोशल मीडिया प्रमुख को भी लगा 21 लाख का चूना

नोएडा। एलइटी विज्ञापन के माध्यम से दुकानदारों से 1.10 लाख निवेश कराकर 10-15 हजार प्रतिमाह मुनाफा देकर धोखाधड़ी मामले में आठ हजार लोगों से 88 करोड़ की धोखाधड़ी होने का अंदेश है। भाजपा सोशल मीडिया व आईटी विभाग प्रमुख तपना मंडल इटावा के साथ भी साढ़े 21 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है।

मुनाफा का झांसा देकर की गई धोखाधड़ी
पीडितों की शिकायत पर फेज वन थाने में 16 के खिलाफ धोखाधड़ी, न्यास भंग के नियमों का दुरुपयोग व धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस आयुक्त गौतमबुद्ध नगर मामले की जांच कर रही है। सुखवेद्र सिंह ने बताया कि दिसंबर 2023 में जुड़ने पर कंपनी में साढ़े 21 लाख रुपये का निवेश किया था। निवेश के एवज में धनराशि प्राप्त नहीं होने पर शिकायत की गई थी।

शिकायत के दौरान हजारों लोगों के रुपये फंसे होने के बारे में पता चला था। उन्होंने जून 2024 में डीसीपी नोएडा, फेस वन थाना पुलिस व अन्य अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। सेक्टर 20 थाना के एक दारोगा ने भी शिकायत में अड़ंगा डाला।

कंपनी की ओर से धनराशि लौटाने में बाधा का काम किया जबकि दारोगा को पीडितों की मदद करनी चाहिए थी। इसी के चलते कंपनी पदाधिकारियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कंपनी पदाधिकारियों व स्टाफ के चंगुल में आठ हजार से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका जताई

है। पीडितों ने बताया कि कंपनी पदाधिकारियों व स्टाफ की ओर से पंजीकृत होने की जानकारी दी गई थी।

डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से कंपनी से जुड़े
कंपनी की ओर से निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए प्रचार प्रसार भी किया गया। इसी झांसे में आकर निवेशक निवेश कर रहे हैं। निवेशक 1.10 लाख से लेकर कई स्टाफ के आधार पर निवेश कर रहे हैं। सुखवेद्र सिंह ने बताया कि वह कंपनी से दिसंबर 2023 में डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से जुड़े थे। अपने साथ 16 से ज्यादा जानकारों को निवेश कराया था।

शुरुआत में दो दिन माह तक किराये के नाम पर धनराशि प्राप्त हुई। इस बीच कंपनी प्रतिनिधियों की ओर से भी एलइटी व निवेश धनराशि मुनाफा प्राप्त होने को लेकर भी फीडबैक लिया था। उसके बाद धनराशि प्राप्त नहीं होने पर शिकायत करने पर टरकाया गया।

निवेशकों की ओर से आइजीआरएस पर शिकायत की गई तो कंपनी पदाधिकारियों ने पुलिस के माध्यम से गठजोड़ कर प्राप्त की आख्या सभी शिकायतों के निस्तारण में लगा दी।

मध्य प्रदेश में 2022 में 200 लोगों से तीन करोड़ टगे

सुखवेद्र सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश में इसी तरह वर्ष 2022 में 200 लोगों से तीन करोड़ रुपये की ठगी थी। वहां ठगी करने वाले कंपनी में आरोपित विनोद जाटव उर्फ अनुज हैं।

नोएडा में फिर गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, अवैध दुकानों पर हुई कार्रवाई; दी गई कड़ी चेतावनी

नोएडा प्राधिकरण ने जिले के सेक्टर-76 स्थित आम्रपाली प्रिंसले सोसायटी के बाहर बड़े पैमाने पर किए गए अतिक्रमण (बुलडोजर कार्रवाई) को हटा दिया है। इस कार्रवाई में चार जेसीबी 50 से अधिक कर्मचारी और भारी पुलिस बल शामिल था। इस दौरान लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि दोबारा यहां दुकानें लगाईं तो एफआईआर दर्ज होगी।

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर सेक्टर-76 स्थित आम्रपाली प्रिंसले सोसायटी के बाहर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर दुकानों का संचालन किया जा रहा था, जिसे बृहस्पतिवार को वर्क सिकिल-6 की टीम ने हटा दिया। दोपहर बाद तक सिकिल अधिकारी की अगुवाई में कार्रवाई जारी रही। इसमें चार जेसीबी, 50 से अधिक कर्मचारियों के साथ भारी पुलिस बल शामिल रहा।

हालांकि इस कार्रवाई के विरोध में कुछ लोगों ने अपना आक्रोश प्रकट किया, लेकिन मौजूद पुलिस बल के आगे उनके एक न चली। बता दें कि यहां पर लगातार सोसायटी के निवासियों की ओर से प्राधिकरण में शिकायत मिल रही थी कि देर रात तक यहां पर दुकानों का संचालन होता है। इससे काफी परेशानी होती है।

50 से ज्यादा दुकानों को किया गया ध्वस्त

ऐसे में प्राधिकरण ने टीम बृहस्पतिवार को सोसायटी के बाहर लग रहे अवैध बाजार को ध्वस्त करने पहुंची। इसमें अवैध रूप से बना ढाबा और करीब 50 से ज्यादा दुकानों



को ध्वस्त किया गया। डंपर में रेहड़ी ठेली समेत सामान को रख कर जब्त किया। इसके बाद तोड़फोड़ टीम अंतरिक्ष गोल्फ व्यू-1 सोसायटी पहुंची। यहां से भी 40 दुकानों को हटाया।

अतिक्रमणकर्ताओं को चेतावनी दी कि दोबारा यहां दुकानें लगाईं तो एफआईआर दर्ज होगी। वर्क सिकिल छह वरिष्ठ प्रबंधक केबी सिंह ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है।

सिकिल में जितनी भी सोसायटी है सभी स्थानों पर इस तरह का अभियान लगातार चलाया जाएगा। इस मौके पर जितने भी जागह पर रैप पर अवैध कब्जा मिला, उसे हटाया गया।

'मैं बुलडोजर चलाऊंगा, चाहे मुझे फांसी क्यों न हो जाए', आखिर क्यों भड़के BJP विधायक नंद किशोर गुर्जर ?

गाजियाबाद के लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने रेप की घटना को लेकर अपने ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद से अपराध में वृद्धि हुई है। अगर एक हफ्ते के भीतर रेप के आरोपी के घर नहीं ढहाए गए तो वह खुद बुलडोजर लेकर निकलेंगे चाहे उन्हें फांसी क्यों न हो जाए।



इज्जत लूट रहे हैं, लेकिन पुलिस अपने-अपने दफतरो में बैठे हुए हैं। अगर इनसे हमें ही लड़ना है तो पुलिस की जूरत क्या है?

कमिश्नरी सिस्टम ने बेड़ा गर्क किया: नंद किशोर गुर्जर

उन्होंने कहा कि लोनी में ये हालत हो गई है कि यहां घरों में घुसकर लूटपाट की जा रही है। पूरे गाजियाबाद में चैन छीना, कूरना, चोरी और कल्ल करना अब आम बात है। हम चाहते हैं कि कमिश्नरेट सिस्टम खत्म किया जाए और दोबारा से कप्तान सिस्टम लागू हो। पहले यहां क्राइम नहीं था। पिछले दो साल में कमिश्नरी सिस्टम में बेड़ा गर्क कर दिया। आम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है।

सरकार आरोपी के घर चलाए बुलडोजर: नंद किशोर गुर्जर

नंद किशोर गुर्जर ने चेतावनी दी और कहा कि लोनी की हर महिला और मेरी बहन और बेटा है। अगर किसी के दुराचार हुआ है तो ये मेरे लिए डूब मरने की बात है। पुलिस के कान बंद हैं। जो बड़े अधिकारी ये सोच रहे हैं कि वो यहां वायसराय बनकर हाहाकार करेंगे। तो लोनी में ये नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर यहां बुलडोजर नहीं चला तो मैं खुद बुलडोजर लेकर निकलूंगा, चाहे मुझे इसके लिए जेल ही क्यों न जाना पड़े। या फिर सरकार खुद आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाए।

आरक्षण खत्म करने की बात कौन करेगा ?

अशोक मधुप

प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण को लेकर कर्नाटक सरकार ने यूटर्न ले लिया है। सरकार ने पहले सी और डी कैटेगरी की प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की बात कही थी। फिलहाल, आरक्षण के उस फैसले पर रोक लगा दी गई है।

लित और पिछड़े युवाओं के उत्थान के लिए लाया गया आरक्षण अब सत्ता में पहुंचने के माध्यम बनता जा रहा है। अलग-अलग राज्य में राजनैतिक दल जहां आरक्षण को अपने हिसाब से अदल-बदल रहे हैं, वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की कोशिश हो रही है। कुछ राज्यों ने अपने यहां ये आरक्षण लागू किया पर वहां के हाईकोर्ट ने उसे अवैध बताते हुए रोक लगा दी, पर ये कोशिश जगह-जगह जारी है।

सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायधीशों की संविधान पीठ आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने की बात की तो विपक्ष ने राजनैतिक लाभ उठाने के लिए इसका विरोध शुरू कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वस्त कर चुके हैं कि आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू नहीं होगा, इसके बावजूद आरक्षण समर्थक राजनैतिक दलों ने इसके विरुद्ध आंदोलनरत हैं। अभी वे भारत बंद का आह्वान कर ही चुके हैं। इससे पहले कर्नाटक में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय के लिए आरक्षण को लागू करने पर खड़ा हो गया। हालांकि प्रदेश कैबिनेट में पास किया गया ये कानून विरोध को देखते हुए ठंडे बस्ते में डाल

दिया गया है, पर खत्म नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर फिर विचार होगा।

हाल के लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के आते-आते प्रचार आरक्षण पर आकर सिमट गया। भाजपा नेता अपने भाषणों में दावा कर रहे हैं कि हम देश में मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में मुस्लिम आरक्षण पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि सत्ता में आते ही इंडिया गठबंधन दलित और पिछड़ों का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को दे देगा। वे देश का विभाजन करवा देंगे। इस पर कुछ बड़े नेता तो चुप्पी साधे हैं किंतु समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने एक बयान में कहा है कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आते ही संविधान में संशोधन कर मुस्लिमों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा।

देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए। आजादी के बाद दलित समाज को विकास की धारा में शामिल करने के लिए दस साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आज ये आरक्षण राजनेताओं को सत्ता में पहुंचने का माध्यम नजर आने लगा है, वे इसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। खत्म करने की नहीं। किसी को यह सोचने की फुरसत नहीं कि आरक्षण की मार से बचने के लिए देश के प्रतिभाशाली युवा आज विदेशों में जाकर शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा पूरी कर वहीं नौकरी या व्यवसाय कर चुने गए देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। भारत के बाहर जाकर बसी भारत की मेधा से प्रभावित होते देश के विकास पर किसी को सोचने का समय नहीं।

प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण को लेकर कर्नाटक सरकार ने यूटर्न ले लिया है। सरकार ने पहले सी और डी कैटेगरी की प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की बात कही थी। फिलहाल, आरक्षण के उस फैसले



पर रोक लगा दी गई है। कैबिनेट ने फैसला स्थगित कर दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्राइवेट सेक्टर में कन्नड़ लोगों को 100 फीसदी आरक्षण देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी। अपनी इस पोस्ट में उन्होंने कहा, हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध होने पर इस पर रोक लगा दी गई। सरकार का कहना है कि इस बिल पर वह पुनर्विचार करेगी। देश में यह पहला ऐसा मामला नहीं है।

कर्नाटक से पहले प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए आंध्र प्रदेश और हरियाणा में कोशिश की गई थी। वहीं, मध्य प्रदेश में भी सरकार ने ऐसा ही कहा था, लेकिन यह कोशिश रंग नहीं ला पाई थी। 2019 में आंध्र

प्रदेश में पहली बार ऐसा कोई कानून बना था जहां 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही गई थी। पर हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। फिलहाल, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। महाराष्ट्र में 2019 में शिवसेना-कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की सरकार बनने के बाद प्राइवेट नौकरियों में स्थानीयों को 80 प्रतिशत नौकरियों देने का प्रस्ताव लाया गया था। सरकार प्राइवेट नौकरियों में स्थानीयों को 80 प्रतिशत नौकरियों देने का प्रस्ताव लाया गया था। सरकार नवंबर में इस कानून को रद्द कर दिया। झारखंड में दिसंबर 2023 में हेमंत सोरेन की सरकार ने सरकारी नौकरियों की युप तीन और चार में स्थानीयों को 100 प्रतिशत आरक्षण देने के मकसद से बिल पास किया था। ये बिल विधानसभा में पास हो गया था, लेकिन गवर्नर ने

सरकार कोशिश कर चुकी है। वहीं अक्टूबर 2020 में यंदियुप्पा की अगुवाई में बीजेपी सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में गुप सी और डी में 75 प्रतिशत आरक्षण स्थानीयों को देने का ऐलान किया था। हालांकि, ये लागू नहीं हो सका था।

हरियाणा में 2020 में तब की मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीयों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून पास किया था। हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस कानून को रद्द कर दिया। झारखंड में दिसंबर 2023 में हेमंत सोरेन की सरकार ने सरकारी नौकरियों की गुप तीन और चार में स्थानीयों को 100 प्रतिशत आरक्षण देने के मकसद से बिल पास किया था। ये बिल विधानसभा में पास हो गया था, लेकिन गवर्नर ने

इसे लौटा दिया था।

आज के हालात का निष्कर्ष ये है कि प्रत्येक दल आरक्षण की सीढ़ी से सत्ता में पहुंचने के प्रयास में लगा है। उसे उससे वास्ता नहीं कि आरक्षण की जद में आने वाली प्रतिभाएं इसे लेकर क्या सोचती हैं? 2012 में केंद्र सरकार प्रमोशन में आरक्षण का बिल ला चुकी है। संसद में बिल रखे जाने के दौरान एक सांसद द्वारा मंत्री से छीन कर बिल की प्रति फाड़ दिए जाने के कारण ये अटक गया। नहीं तो प्रमोशन में भी आरक्षण लागू हो चुका होता।

अब क्रीमीलेयर तै करने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के आदेश को वे ही ठेगा दिखाने को तैयार हैं जो अब तक इससे लाभ लेते रहे हैं। आरक्षण का लाभ उठा चुके उच्च स्थिति में पहुंचने वाले ही विकास की धारा में वंचित अपनी जाति वालों के लिए आरक्षण का लाभ छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

आज हालत यह है कि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ आदेश करे या कोई अन्य मांग हो, आरक्षण को कम करने को कोई राजनैतिक दल छोड़ने को तैयार नहीं। कोई इसके खत्म करने की बात नहीं कर रहा। सब बढाने की बात कर रहे हैं। आरक्षण के दायरे से बाहर की जाति और उसे युवा ये सब देख रहे हैं। अभी हाल में यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर हुए बवाल ने बाद सरकार ने 45 पदों पर लेटरल एंट्री का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। विपक्ष का कहना था कि सरकार आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, सरकार अपनी छवि बचाने को बाल-बाल पीछे हटती जा रही है। ऐसे में आरक्षण से बाहर रह रही युवा पीढ़ी के कथिप्य की किसी की चिंता नहीं। आरक्षण समर्थक कोई नेता और राजनैतिक दल ये नहीं सोच रहा कि ये आरक्षण से बाहर रहे युवा उनके बारे में क्या विचार और सोच बना रहे हैं?

ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का तीसरा दिन

परिवहन विशेष न्यूज

रांची के 20 किलोमीटर के दायरे में ऑटो चलाने के नियमों में बदलाव के विरोध में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज गुरुवार, 29 अगस्त को तीसरा दिन है। ऑटो और ई-रिक्शा सड़क से गायब हो गए हैं। रांची के 12,500 ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है। कई लोग पैदल ही अपने गंतव्य तक जा रहे हैं, जबकि कुछ

लोग ओला, रैपिडो आदि का सहारा ले रहे हैं। दरअसल, रांची की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शहर के 20 किलोमीटर के दायरे में ऑटो चलाने के नियमों में बदलाव किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो परिचालन के रूट को चार जोन में बांटकर 3-3 किलोमीटर का दायरा बनाया है, जिसके विरोध में 10 हजार से अधिक ऑटो और 2500 ई-रिक्शा चालक मंगलवार 27 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो

चालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी ने बताया कि ऑटो चालक खुद सड़कों पर उतरकर ऑटो का परिचालन बंद कर रहे हैं। ऑटो चालक महासंघ के अनुसार पहले ऑटो चालक 17 किलोमीटर के दायरे में परिचालन करते थे, लेकिन नए नियमों में सिर्फ 3 किलोमीटर के दायरे में ही ऑटो परिचालन की अनुमति दी गई है, जो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। ऑटो चालकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक किसी भी रूट पर ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन नहीं होगा।



एनएच-9 के बाद अब हापुड़ रोड पर भी नहीं चलेंगे ई-रिक्शा, एक सितंबर से लागू होगी नई व्यवस्था

परिवहन विशेष न्यूज

एनएच-9 के बाद अब हापुड़ रोड पर भी ई-रिक्शा का संचालन बंद हो जाएगा। इसके लिए पुलिस ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। यह नियम एक सितंबर से लागू हो जाएगा। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।

कम स्पीड के कारण ई-रिक्शा मुख्य मार्ग पर यातायात में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। इसी कारण पुलिस ने एनएच-9 पर ई-रिक्शा के प्रवेश पर रोक लगा दी है, अब हापुड़ रोड पर भी ऐसा करने की तैयारी है। पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा ने बताया कि एक सितंबर से पुराने बस अड्डे से डासना आर ओबी के बीच ई-रिक्शा का संचालन बंद करने का निर्णय लिया गया है। इससे हापुड़ रोड पर यातायात सुचारू हो सकेगा। वैसे भी भारी ट्रैफिक के कारण हापुड़ पर ई-रिक्शा का संचालन सुरक्षित नहीं है। एक सितंबर से हापुड़ रोड पर ई-रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित कर दी जाएगी।

पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा ने बताया कि हापुड़ रोड के कनेक्टिंग रोड पर ई-रिक्शा चलते रहेंगे, लेकिन हापुड़ रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लोगों को ऑटो या बस का सहारा लेना पड़ेगा। गलियों से हापुड़ रोड पर आने के लिए ई-रिक्शा का इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि नए बस अड्डे से पुराने नए बस अड्डे के बीच ई-रिक्शा का संचालन जारी रखने का फैसला लिया गया है। पुलिस लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि शहर के यातायात को कैसे सुचारू रखा जाए। पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा ने बताया कि ई-रिक्शा चालकों और आम जनता को



जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस तीन दिन तक जागरूकता अभियान चलाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि एक सितंबर से हापुड़ रोड पर ई-रिक्शा का संचालन बंद कर दिया जाएगा। जागरूकता से नई व्यवस्था को लागू करने में आसानी होगी और लोग इसके लिए पहले से तैयार रहेंगे। इसके लिए जिला पुलिस को ई-रिक्शा चालकों से समन्वय स्थापित कर नई व्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए हैं। ई-रिक्शा चालकों को बताया जाए कि हापुड़ रोड के दोनों ओर 50

मीटर तक ही संचालन की अनुमति होगी। एडीसीपी पीयूष सिंह ने बताया कि नो एंट्री जोन में ई-रिक्शा आने पर ट्रैफिक पुलिस उसे सीज करने की कार्रवाई करेगी। फिलहाल एनएच-9 पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है। एक सितंबर से पुराने बस स्टैंड से डासना आर ओबी के बीच हापुड़ रोड पर कोई भी ई-रिक्शा चलता मिला तो उसे सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। नो एंट्री जोन में ई-रिक्शा को सड़क किनारे खड़ा नहीं होने दिया जाएगा।

एडीसीपी पीयूष सिंह ने बताया कि हापुड़ रोड शहर की मुख्य सड़क है। इस सड़क पर रोडवेज और पब्लिक बसों का संचालन होता है। मुर्शिदाबाद, रामपुर, बरेली और हल्द्वानी, नैनीताल की ओर जाने वाली रोडवेज बसें इसी सड़क पर संचालित होती हैं, ऐसे में ई-रिक्शा के संचालन से हादसों का खतरा बना रहता है और ई-रिक्शा कई सड़कों पर जाम का कारण भी बन रहे हैं। इसलिए हापुड़ रोड पर धीमी गति से चलने वाले ई-रिक्शा का संचालन बंद करने का निर्णय लिया गया है।

थाईलैंड में होंडा सीटी125 दो नए कलर ऑप्शन में हुई लॉन्च, कीमत में नहीं किया गया इजाफा

परिवहन विशेष न्यूज

Honda ने अपनी पॉपुलर बाइक CT125 को थाईलैंड बाजार में नए कलर स्कीम में लॉन्च किया है। जिन दो नए कलर ऑप्शन में इसे लॉन्च किए गए हैं वो पर्ल स्मोकी ग्रे और पर्ल शुगरकेन बेज है। यह एक सिटी बाइक है जिसका इस्तेमाल कुछ राइडर्स लंबी दूरी के लिए भी करते हैं। आइए जानते हैं कि किन फीचर्स के साथ आती है।

नई दिल्ली। होंडा ने अपनी पॉपुलर छोटी डिस्लेसमेंट मोटरसाइकिल CT125 को नए कलर ऑप्शन में पेश किया है। इस बाइक को कम पावर लेकिन वसंदाइल और व्यावहारिक प्रकृति के लिए जाना जाता है। यह भारत ही नहीं, बल्कि थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में काफी पॉपुलर है। वहीं, इसे नए कलर स्कीम में थाईलैंड बाजार में पेश किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

सिटी बाइक के रूप में बेहद पॉपुलर होंडा CT125 एक सिटी बाइक है, लेकिन कुछ ऐसे राइडर भी हैं जो इसका इस्तेमाल लंबी दूरी तय करने के लिए करते हैं। जापानी



कंपनी ने इसके टॉप बॉक्स और सैडल बैग जैसे कई लगेज ऑप्शन भी डेवलप किए हैं। अब इसे एक एम्बीशियस टू-व्हीलर ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। यह काफी हल्की होने के साथ ही फ्यूल एफिशिएंसी भी है।

दो नए कलर ऑप्शन में आई अपडेटेड होंडा CT125 को दो नए कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जो पर्ल स्मोकी ग्रे और पर्ल शुगरकेन बेज है। यह फुल-प्रोडक्शन मॉडल है। सबसे अच्छी बात यह है कि होंडा ने CT125 को दो नए कलर ऑप्शन में पेश करने के बाद भी इसकी कीमत में बढ़ोतरी नहीं की है। जिसे देखते

उम्मीद है कि इसकी बिक्री में बढ़ोतरी हो सकती है।

भारतीय खरीदारों को नहीं कर पर आकर्षित

CT125 जैसे टू-व्हीलर को भारतीय बाजार में नए और युवा खरीदारों को आकर्षित करने के लिए होंडा नवी के साथ ऐसा करने की कोशिश की थी। हालांकि, कंपनी यहां पर ऐसा करने में विफल रही। उसके बाद से होंडा इंडिया ने नई कॉन्सेप्ट के साथ प्रयोग नहीं किया है। ऐसी कई बाइक है जिसकी भारत में कीमत अधिक है, जिसकी वजह से भारतीय खरीदारों को इसे खरीदने पर विचार करने के लिए सोचना पड़ता है।

वीरा वाहना, एक्सपोनेंट एनर्जी ने 'दुनिया की पहली 15 मिनिट की चार्जिंग वाली इंटरसिटी बस' की घोषणा की

परिवहन विशेष न्यूज

कंपनियों द्वारा जारी एक संयुक्त प्रेस विज्ञापन में एक्सपोनेंट एनर्जी के साथ साझेदारी में वीरा वाहना ने एक लंबी दूरी की इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस की घोषणा की है जो 15 मिनट में तेजी से चार्ज हो जाती है। एक्सपोनेंट द्वारा संचालित 'वीरा महासम्राट ईवी' दुनिया की पहली 2-एक्सल 13.5 मीटर इलेक्ट्रिक बस है।

विज्ञापन में कहा गया है "यह एक्सपोनेंट के 320 किलोवाट बैटरी पैक से सुसज्जित है, जो एक्सपोनेंट के 15MW चार्जिंग नेटवर्क के माध्यम से 15 मिनट की फास्ट चार्जिंग के साथ लगभग असीमित रेंज प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, 6,00,000 किमी या 3000 बैटरी जीवन चक्र की बैटरी वारंटी बेहतर वित्तीयता विकल्पों और स्वामित्व में आसानी का मार्ग प्रशस्त करती है।"

कंपनियों ने दावा किया कि वीरा महासम्राट ईवी के साथ, बेड़े के मालिक आईसीई बस की तुलना में अपने परिचालन व्यय को 30% तक कम कर सकते हैं। "पहली बार, 15 मिनट की रैपिड चार्जिंग और राजमार्गों के साथ एक्सपोनेंट चार्जिंग नेटवर्क के साथ, बस ऑपरेशन अब लंबी दूरी के अंतर-शहर मार्गों पर इलेक्ट्रिक जा

सकते हैं, बिना रेंज और लंबे चार्जिंग समय के बारे में चिंता किए।"

वर्तमान में दोनों कंपनियाँ बेंगलुरु-हैदराबाद मार्ग को विद्युतीकृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। परिचालन का समर्थन करने के लिए, एक्सपोनेंट एनर्जी चार 1 मेगावाट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी - प्रत्येक एंडपॉइंट पर दो और राजमार्ग पर दो। विज्ञापन में कहा गया है, "इससे यह सुनिश्चित होगा कि बस ऑपरेशन स्टॉप की संख्या और प्रति स्टॉप डाउनटाइम के समान अनुभव के साथ आईसीई से इलेक्ट्रिक में सहजता से स्थानांतरित हो सकें।"

वीरा वाहना के प्रबंध निदेशक के. श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, "आज, सीमित रेंज और लंबे चार्जिंग समय के कारण इलेक्ट्रिक बसें कम दूरी या इंद्रासिटी संचालन तक ही सीमित हैं। 600 किमी की रेंज देने के लिए एक बैटरी को पैकेज करना मुश्किल है और लंबे चार्जिंग समय के साथ -ग्राहक राजमार्ग पर एक घंटे तक इंतजार करने को तैयार नहीं हैं। आम तौर पर, डीजल बसें हर 300 किमी पर 15-20 मिनट के लिए रुकती हैं और एक्सपोनेंट के साथ हमारी अनुभूति साझेदारी उसी अनुभव की नकल करती है। अब, बस ऑपरेशन

वीरा महासम्राट ईवी के साथ सहजता से इलेक्ट्रिक पर स्विच कर सकते हैं और अपने संचालन में अधिक बचत कर सकते हैं।" कंपनी का प्रौद्योगिकी स्टैक अपने मालिकाना ऑफ-बोर्ड थर्मल प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके अपने बीएमएस, चार्जिंग एल्गोरिथम और थर्मल प्रबंधन के माध्यम से प्रत्येक सेल की विशेषताओं का प्रबंधन करता है, जहाँ चार्जिंग स्टेशन इष्टतम तापमान बनाए रखने के लिए चार्ज करते समय बैटरी में सक्रिय रूप से शीतलक पंप करता है और इस प्रकार 50 डिग्री सेल्सियस तक के परिवेश के तापमान पर भी लगातार प्रदर्शन प्रदान करता है।

घोषणा पर टिप्पणी करते हुए एक्सपोनेंट एनर्जी के सह-संस्थापक और सीईओ अरुण विनायक ने कहा, "हम बस उद्योग में एक अनुभवी खिलाड़ी वीरा वाहना के साथ साझेदारी करके उत्साहित हैं, ताकि लंबी दूरी की इंटरसिटी बस सेगमेंट को वास्तव में विद्युतीकृत किया जा



सके। हम टेस्ला और सीमेंस के बाद भारत में, भारत के लिए दुनिया की तीसरी 1 मेगावाट चार्जिंग तकनीक बनाने के लिए रोमांचित हैं। 15 मिनट की रैपिड चार्जिंग

और एक्सपोनेंट नेटवर्क द्वारा दी गई स्वतंत्रता और पहुंच के साथ, हम पूरे भारत को इलेक्ट्रिक बनाने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

चार्जप्वाइंट ने चार्जर की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एआई टूल किया लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

चार्जप्वाइंट ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के निदान और मरम्मत को बढ़ाने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व एआई-संचालित ड्राइवर सहायता उपकरण का अनावरण किया है। यह नवाचार ईवी चार्जिंग उद्योग में एआई के पहले उपयोग को चिह्नित करता है, जो चार्जिंग स्टेशनों के अपटाइम और विश्वसनीयता में काफी सुधार करता है। नया सॉफ्टवेयर, जो चार्जप्वाइंट के मौजूदा बुनियादी ढांचे में सहजता से एकीकृत होता है, चार्जिंग स्टेशन की विश्वसनीयता को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्य बातें: ईवी चार्जिंग उद्योग में चार्जर संबंधी समस्याओं के निदान और मरम्मत के लिए पहला एआई-संचालित समाधान। उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस ड्राइवरों को चार्जप्वाइंट ऐप के माध्यम से फोटो सबमिट करके समस्याओं की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। एआई सॉफ्टवेयर छवियों का विश्लेषण करता है और विस्तारित की पहचान करता है, तथा समस्या को चालक के

स्थान से जोड़ता है।

समस्याओं को चार्जप्वाइंट के नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर तक पहुंचाया जाता है, जिससे साइट पर निरीक्षण की आवश्यकता कम हो जाती है और मरम्मत का समय भी कम हो जाता है।

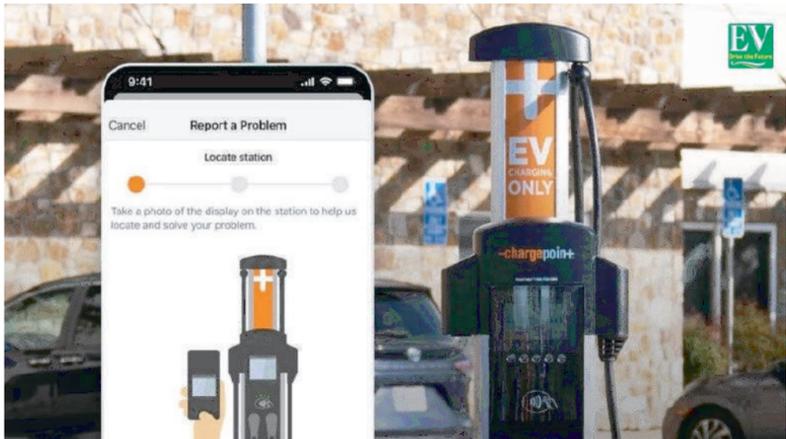
ड्राइवरों के लिए ऐप में वास्तविक समय की मरम्मत स्थिति ट्रैकिंग उपलब्ध है। मरम्मत प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए स्टेशन मालिकों के लिए स्वचालित अलर्ट तैयार किए जाते हैं।

चार्जप्वाइंट के सीईओ रिक विल्मर ने इस प्रगति के महत्व पर जोर दिया रहा ड्राइवर समस्याओं का निदान करने वाली एआई तकनीक को तेनात करके, चार्जप्वाइंट के पास स्टेशन अपटाइम सुनिश्चित करने के लिए हमारे नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर में शामिल होने वाला एक महत्वपूर्ण नया टूल है। यह तकनीक हमें उन भौतिक समस्याओं को प्राथमिकता देने और हल करने में सक्षम बनाएगी जिन्हें रिमोट मॉनिटरिंग के माध्यम से पता नहीं लगाया जा सकता है, जो एक विश्वसनीय चार्जिंग नेटवर्क प्रदान करने वाले नवाचारों के

प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

यह नई सुविधा ड्राइवरों को एक उन्नत ऐप इंटरफ़ेस के माध्यम से गैर-कार्यात्मक चार्जिंग स्टेशन के साथ किसी समस्या की आसानी से रिपोर्ट करने की अनुमति देती है। एक बार जब एआई सॉफ्टवेयर समस्या की पहचान कर लेता है, तो यह तुरंत चार्जप्वाइंट की संचालन टीम को सूचना भेजता है, जिससे अक्सर भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और मरम्मत का समय काफी कम हो जाता है। ऐप ड्राइवरों को मरम्मत की स्थिति को ट्रैक करने और स्टेशन के मालिक को स्वचालित रूप से सूचित करने की अनुमति देकर भी सूचित रखता है, जो अक्सर मरम्मत के लिए आवश्यक प्राथिकरण प्रक्रिया को गति देता है।

चार्जप्वाइंट होल्डिंग्स, इंक. ईवी चार्जिंग समाधान का एक अग्रणी प्रदाता है, जो 2007 से एक विश्वसनीय और व्यापक चार्जिंग नेटवर्क बनाने के लिए समर्पित है। उनका अभिनव क्लाउड सदस्यता प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर-परिभाषित चार्जिंग हार्डवेयर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में विश्वसनीय चार्जिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है।



AI और न्यू एनर्जी अब रिलायंस का नया मंत्र, आम आदमी के लिए तकनीक सुलभ करने पर रहेगा फोकस

परिवहन विशेष न्यूज

रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस का न्यू एनर्जी कारोबार चालू होने के 5 से 7 वर्षों में ही उतनी कमाई करने लगेगा जितनी हमारा तेल गैस या रसायन वाला कारोबार करता है। कंपनी ने कच्छ में बंजर भूमि को पट्टे पर लिया है। इस बंजर भूमि में अगले 10 वर्षों में लगभग 150 अरब यूनिट बिजली पैदा होगी।

नई दिल्ली: पिछले कुछ वर्षों से देश का प्रमुख उद्योग समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) अपने कारोबार की प्रकृति में बदलाव का संकेत दे रही थी और गुरुवार को कंपनी की 47वें सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस बारे में विधिवत घोषणा कर दी। उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और नई प्रौद्योगिकी कंपनी का नया मूल मंत्र होगा।

रिलायंस ग्रुप की कंपनी जियो ब्रेन जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लांच करेगी। कनेक्टेड इंटेलिजेंस, विश्व स्तरीय इंफ्रा के साथ यह सर्विस "एआई एक्सीटिव फॉर एक्सीटिव" की थीम पर यह लांच होगी, जिसका इस्तेमाल आम आदमी आसानी से कर सकेगा। कंपनी ने हर शेयर पर एक शेयर बतौर बोनस देने का एलान किया है। 15 सितंबर, 2024 को निदेशक बोर्ड की बैठक में इसे मंजूरी मिलने की संभावना है।

रिलायंस में छंटनी की खबरों को खारिज किया

रिलायंस ने लाखों लोगों को दी नौकरी की सौगात, कंपनी में कर्मचारियों की तादाद बढ़कर हुई 6.5 लाख

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आज 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है। यह मीटिंग दोपहर 2 बजे से शुरू हुई है। मीटिंग में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने नौकरियों में कटौती को लेकर अपनी बात रखी। मुकेश अंबानी ने कंपनी में नौकरियों में कटौती की खबरों को खारिज करते हुए इसे भ्रामक बताया। मुकेश अंबानी ने जानकारी दी कि रिलायंस ने वित्त वर्ष 2023-24 में लाखों नौकरियां जोड़ी हैं।

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आज 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है। यह मीटिंग दोपहर 2 बजे से शुरू हुई है। मीटिंग में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने नौकरियों में कटौती की खबरों को खारिज करते हुए इसे भ्रामक बताया। मुकेश अंबानी ने जानकारी दी कि रिलायंस ने वित्त वर्ष 2023-24 में लाखों नौकरियां जोड़ी हैं। मुकेश अंबानी ने बताया कि रिलायंस ने कुल 1.7 लाख नई नौकरियां दी हैं। कंपनी के

कुल कर्मचारियों की संख्या बढ़कर अब 6.5 लाख से अधिक हो गई है। **कर्मचारियों की संख्या में दिखी थी कमी** बता दें, पिछले वित्त वर्ष में जियो की वार्षिक रिपोर्ट में कर्मचारियों की संख्या में कमी दिखाई दी थी। इस कमी पर मुकेश अंबानी ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या में गिरावट की वजह कर्मचारियों द्वारा नौकरी के एक अलग मॉडल चुनाव था। उन्होंने कर्मचारियों को निकाले जाने की बात को स्वीकार नहीं किया था।

इस पर उन्होंने कहा रोजगार सृजन की प्रकृति वैश्विक स्तर पर बदल रही है, जिसका मुख्य कारण तकनीकी हस्तक्षेप और लचीले व्यापार मॉडल हैं। इसलिए, सिर्फ पारंपरिक प्रत्यक्ष रोजगार मॉडल के बजाय, रिलायंस नए प्रोत्साहन-आधारित जुड़ाव मॉडल को अपना रहा है। इससे कर्मचारियों को बेहतर कमाई करने में मदद मिलती है और उनमें उद्यम की भावना पैदा होती है। यही कारण है कि प्रत्यक्ष रोजगार संख्या वार्षिक आंकड़ों में थोड़ी गिरावट दिखाई है, हालांकि रिलायंस द्वारा सृजित कुल रोजगार में वृद्धि हुई है।

सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए नया सरलीकृत पेंशन फॉर्म जारी करेगा केंद्र



सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी जो ई-एचआरएमएस पर हैं। वे ई-एचआरएमएस के माध्यम से फार्म 6-ए भरेंगे और जो ई-एचआरएमएस पर नहीं हैं वे भविष्य पोर्टल पर फार्म 6-ए भरेंगे। विज्ञापित के अनुसार इस नए फॉर्म और भविष्य/ई-एचआरएमएस के साथ इसका एकीकरण 30 अगस्त को केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जारी किया जाएगा। इस नए फॉर्म में कुल नौ फार्म/प्रारूपों को मिला दिया गया है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार को अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक नया सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी करेगा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने 16 जुलाई, 2024

की अपनी अधिसूचना के जरिए सरलीकृत पेंशन आवेदन "फार्म 6-ए" जारी किया था। कार्मिक मंत्रालय की ओर से गुरुवार को एक बयान में कहा गया- "यह फार्म भविष्य/ई-एचआरएमएस (आनलाइन माह्यूल) में केंद्र सरकार के उन सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो दिसंबर 2024 और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी जो ई-एचआरएमएस पर हैं, वे ई-एचआरएमएस के माध्यम से फार्म 6-ए भरेंगे और जो ई-एचआरएमएस पर नहीं हैं, वे भविष्य पोर्टल पर फार्म 6-ए भरेंगे। विज्ञापित के अनुसार, इस नए फार्म और भविष्य/ई-एचआरएमएस के साथ इसका एकीकरण 30 अगस्त को केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह



होगी। साथ ही इस साल के अंत तक सौर ऊर्जा में इस्तेमाल होने वाले फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल का उत्पादन शुरू कर देंगे। अगली तिमाहियों में पूरा एकीकृत सौर उत्पादन सुविधाओं का पहला चरण पूरा हो जाएगा। इसमें मॉड्यूल, सेल, ग्लास, वेफर, इंगोट और पॉलीसिलिकॉन शामिल हैं, जिनकी शुरुआती वार्षिक क्षमता 10 गीगावॉट है। जामनगर में 30 गीगावॉट वार्षिक क्षमता वाली

एक एकीकृत उन्नत रसायन-आधारित बैटरी विनिर्माण सुविधा का निर्माण शुरू कर दिया है। अगले साल की दूसरी छमाही तक उत्पादन शुरू हो जाएगा।

बायो एनर्जी से पैदा होंगी 30 हजार नौकरियां

न्यू एनर्जी बिजनेस के बारे में बताते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि, "बायो-एनर्जी कारोबार तेजी से विस्तार कर रहा है और 2025 तक 55

ऑपरेटिंग कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट तक पहुंच जाएगा, जिससे किसान अन्ना दाता से ऊर्जा दाता बन जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में 30,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। कंपनी न्यू एनर्जी बिजनेस में 75,000 करोड़ तक के निवेश के लिए तैयार है।

कंपनी की भावी एआई तैयारियों के बारे में अंबानी ने कहा कि एआई को कवर करने वाले उपकरणों और प्लेटफॉर्मों का एक व्यापक सूट "जियो ब्रेन" विकसित कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि रिलायंस के भीतर जियो ब्रेन को बेहतर बनाकर, हम एक शक्तिशाली एआई सेवा प्लेटफॉर्म बनाएंगे हम जामनगर में गीगावाट-स्केल एआई-तैयार डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, जो पूरी तरह से रिलायंस की हरित ऊर्जा से संचालित होगा। हमारा लक्ष्य यहीं भारत में दुनिया की सबसे किफायती एआई इन्फ्रेस्ट्रक्चर बनाना है। इससे भारत में एआई एप्लिकेशन ज्यादा किफायती हो जाएंगे और यह सभी के लिए सुलभ हो जाएगा।"

अंबानी ने कहा कि उनकी कंपनी का मकसद भारत की इकोनॉमी में दीर्घकालिक लक्ष्यों को देखते हुए परिस्परितियों का निर्माण करना है। कुछ देशों के लिए मुनाफा कमाने में उनकी कंपनी विश्वास नहीं करती। रिलायंस समूह भारतीय ग्राहकों को वैश्विक स्तर के उत्पाद व सेवा देने में भरोसा करती है और यह काम जारी रहेगा। यह भारत को ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना चाहती है और विश्व के पर्यावरण को सुधारने में भी मदद करेगी।

गौतम अदाणी फिर बने देश के सबसे अमीर व्यक्ति, एक साल में 95% बढ़ी संपत्ति

नई दिल्ली: अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी एक बार फिर देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पछाड़ा है। गुरुवार को जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 में गौतम अदाणी 11.6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ शीर्ष पर रहे हैं और बीते एक वर्ष में उनकी संपत्ति में 95 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही है। 2023 में इस सूची में गौतम अदाणी की संपत्ति 4.74 लाख करोड़ रुपये बताई गई थी। पिछले वर्ष जनवरी में अमेरिकी शार्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसेच की रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह की सभी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में बढ़ी गिरावट आई थी।

दूसरे नंबर पर पहुंचे मुकेश अंबानी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार, इस वर्ष 10.14 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर रहे हैं। 2023 में अंबानी 8.08 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ गौतम अदाणी से आगे थे। एचसीएल टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नादर और उनका परिवार 3.14 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर रहा है। पिछले वर्ष वे इस सूची में चौथे स्थान पर थे। सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया का साइरस पूनावाला एक स्थान खिसककर चौथे स्थान पर रहे हैं और उनकी कुल संपत्ति 2.89 लाख करोड़ रुपये बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 2.50 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सन फार्मस्यूटिकल्स के दिलीप सांचवी पांचवें स्थान पर रहे हैं। पिछले वर्ष सांचवी इस सूची में छठे स्थान पर थे।

खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनने की सिफारिश, 60 प्रतिशत तक निर्भरता आयात पर

परिवहन विशेष न्यूज

खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनने या इस आयात को कम करने पर हमारा आयात खिल भी कम हो जाएगा। गत वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने खाद्य तेल के आयात पर 123078 करोड़ रुपये खर्च किए। नीति आयोग के मुताबिक भारत में खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत अभी 19.7 किलोग्राम प्रतिवर्ष है जबकि विकसित देशों में प्रति व्यक्ति यह खपत 25.3 किलोग्राम की है।

नई दिल्ली: नीति आयोग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनने के लिए तिलहन की खरीदारी हर हाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करना, खाद्य तेल के आयात पर शुल्क में बढ़ोतरी, तिलहन के उत्पादन के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाना और तिलहन के बीज की उपलब्धता के लिए हर ब्लाक में एक गांव को तिलहन के बीज वाले गांव के रूप में विकसित करने जैसी कई सिफारिश की है।

आयोग ने फूड इंडस्ट्रीज को घरेलू खाद्य तेल के इस्तेमाल पर इंसेंटिव देने के साथ तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी सेक्टर के साथ सहभागिता की भी सिफारिश की है।

आयोग की यह सिफारिश इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले 20 सालों से भारत खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए संघर्षरत है, लेकिन आयात कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वर्ष 2022-23 में भारत ने 165 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया था। घरेलू स्तर पर खाद्य तेल के होने वाले उत्पादन से सिर्फ 40-45 प्रतिशत जरूरतें पूरी हो पाती हैं। 60 प्रतिशत जरूरत को पूरा करने के लिए हमें आयात करना पड़ता है। खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनने या इस आयात को कम करने पर हमारा आयात बिल भी कम हो जाएगा। गत वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने खाद्य तेल के आयात पर 1,23,078 करोड़ रुपये खर्च किए। नीति आयोग के मुताबिक भारत में खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत अभी 19.7 किलोग्राम प्रतिवर्ष है जबकि विकसित देशों में प्रति व्यक्ति यह खपत 25.3 किलोग्राम की है। देश के विकास के साथ भारत में भी प्रतिव्यक्ति खपत इस स्तर पर पहुंच सकती है और तब खाद्य तेल की घरेलू मांग व आपूर्ति का अंतर वर्ष 2030 तक 2.23 लाख टन तक जा सकता है। मतलब, अगर घरेलू उत्पादन नहीं



बढ़ाया गया तो वर्ष 2030 तक हमें 220 लाख टन आयात करना पड़ सकता है और अगर अमेरिका की तरह 40.3 किलोग्राम की खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत भारत की हो जाती है तो वर्ष 2030 तक 295 लाख टन खाद्य तेल का आयात करना पड़ेगा। ऐसे में मांग व आपूर्ति के इस अंतर को कम करने के लिए देश के उन हिस्सों में भी तिलहन की खेती शुरू करने की जरूरत है जहां अब तक

यह खेती नहीं होती है। बुंदेलखंड जैसे इलाके में बड़े पैमाने पर यह खेती हो सकती है। अभी आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु व महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मुख्य रूप से तिलहन की खेती होती है। आयोग ने पाम ऑयल की खेती के पर्याय को बढ़ाने के लिए भी कहा है। खाद्य तेल के आयात में पाम आयल की बड़ी

हिस्सेदारी है। सरकार खाद्य तेल के आयात पर इसलिए भी शुल्क नहीं बढ़ा पाती है क्योंकि ऐसा करने से खाद्य तेल की खुदरा कीमत बढ़ जाती है जिससे महंगाई प्रभावित होने लगती है। आयात शुल्क बढ़ाने पर घरेलू किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और वे तिलहन के अधिक उत्पादन के लिए आकर्षित होंगे।

किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाएंगे मुकेश अंबानी, बोले- बायो एनर्जी से पैदा होंगी 30 हजार नौकरियां

परिवहन विशेष न्यूज

रिलायंस का न्यू एनर्जी बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है। मुकेश अंबानी ने एजीएम में कहा कि बायो-एनर्जी कारोबार तेजी से विस्तार कर रहा है और 2025 तक 55 ऑपरेटिंग कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट तक पहुंच जाएगा। इससे किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बन जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में 30000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। कंपनी न्यू एनर्जी बिजनेस में 75000 करोड़ का निवेश करेगी।



नई दिल्ली: अरबपति कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) मुकेश अंबानी ने Reliance AGM 2024 में कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने खासकर न्यू एनर्जी सेगमेंट पर काफी जोर दिया। अरबपति कारोबारी ने कंपनी की 47वीं वार्षिक आम बैठक में कहा कि रिलायंस के न्यू एनर्जी कारोबार में ऑयल टु केमिकल (O2C) के बराबर संभावनाएं हैं।

"हमारे न्यू एनर्जी कारोबार में काफी संभावनाएं हैं। यह चालू होने के 5 से 7 साल हमारे ऑयल टु केमिकल बिजनेस के बराबर कमाई करने लगेगा। रिलायंस ने कच्छ में बंजर भूमि को पट्टे (Lease) पर लिया है। हम यहां से अगले 10 साल में लगभग 150 अरब यूनिट बिजली पैदा करेंगे। यह भारत की कुल ऊर्जा आवश्यकता के 10 फीसदी के बराबर होगी।"

मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन

सोलर फोटो-वोल्टाइक का प्रोडक्शन रिलायंस इस साल के अखिर तक अपने सोलर फोटो-वोल्टाइक (PV) मॉड्यूल का प्रोडक्शन भी शुरू कर देगी। मुकेश अंबानी ने कहा, "हम अगली तिमाहियों में अपनी एकीकृत सौर उत्पादन सुविधाओं का पहला चरण पूरा कर लेंगे। इसमें मॉड्यूल, सेल, ग्लास, वेफर, इंगोट और पॉलीसिलिकॉन शामिल हैं। इनकी शुरुआती वार्षिक क्षमता 10 गीगावॉट रहेगी। हमने जामनगर में एक एकीकृत उन्नत रसायन-आधारित बैटरी विनिर्माण सुविधा बना रहे हैं। इससे अगले साल की दूसरी छमाही तक उत्पादन शुरू हो जाएगा।"

किसान से बनेंगे ऊर्जादाता अंबानी ने न्यू एनर्जी बिजनेस के बारे में कहा, "बायो-एनर्जी कारोबार तेजी से विस्तार कर रहा है और 2025 तक 55 ऑपरेटिंग कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट तक पहुंच जाएगा। इससे किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बन जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में 30,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। कंपनी न्यू एनर्जी बिजनेस में 75,000 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए तैयार है।"

फरीदाबाद में अंतिम यात्रा के दौरान दुखद अनुभव: स्वर्ग आश्रम, मवई रोड, नहर पार फरीदाबाद

परिवहन विशेष न्यूज

डॉ. अंकुर शरण। जीते जी ईसान या तो पानी के लिए तरस रहा है या पानी से भरी सड़कों पर फंस रहा है। कुछ ऐसा ही अनुभव हाल ही में फरीदाबाद के नहर पार, गांव मवई के पास एक अंतिम यात्रा के दौरान हुआ। यह देखकर अत्यंत दुख होता है कि हमारे फरीदाबाद की स्थिति छोटी-छोटी लापरवाहियों के कारण बद से बदतर होती जा रही है।

मात्र 50 मीटर की दूरी थी नहर से लेकर अंतिम धाम तक, और बीच की मुख्य सड़क पर करीब एक फुट पानी भरा हुआ था। तीन-चार पानी के टैंकर और पानी की निकासी मशीनें लगी हुई थीं। समय और पैसे की बर्बादी के साथ-साथ, सैकड़ों लोग इस गंदे, बदबूदार और कीचड़ भरे पानी से होकर अंतिम यात्रा में शामिल हुए।

फरीदाबाद में एक बहुत ही अनोखी घटना घटित हुई, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि नहर पार, नहर से ज्यादा पानी सड़कों पर मिलेगा। यह जीवंत उदाहरण मुझे तब देखने को मिला जब हमारे पारिवारिक मित्र का स्वर्गवास हो गया। ब्रेन हेमरेज के कारण उन्हें फरीदाबाद में सही उपचार नहीं मिल पाया और उन्हें एम्स, दिल्ली रेफर किया गया, जहाँ ऑपरेशन के बाद दो-तीन दिन रखा गया, परंतु स्थिति में सुधार नहीं हुआ और 27 अगस्त को उनका देहांत हो गया।

28 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार किया गया, जो कि स्वर्ग आश्रम, मवई रोड, नहर पार फरीदाबाद हुआ। सेक्टर 31 से नहर पार जाना और वहाँ पर सड़कों पर एक से डेढ़ फुट पानी का होना मन को अत्यंत व्यथित कर गया। ऐसा

लगा कि फरीदाबाद में न तो ईसान को सही चिकित्सा मिल पा रही है और न ही अंतिम यात्रा के लिए संघर्ष से बचा जा सकता है।

सैकड़ों लोगों ने विनम्र श्रद्धांजलि दी, लेकिन इस अनुभव ने एक बड़ा प्रश्नचिह्न भी खड़ा किया कि आखिर छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर व्यापक रूप से कार्यवाही करने की आवश्यकता है। किसी भी सड़क पर गड्डे नहीं होने चाहिए और पानी जमा होना तो कतई नहीं। सबसे खतरनाक स्थिति तब बनी जब

गाड़ियाँ इस सड़क से पार कर रही थीं, और बीच में न फंसने की कोशिश में लोग अपनी गाड़ियों की गति तेजी से बढ़ा रहे थे। इससे पानी में लहरें उत्पन्न हो रही थीं, जो लोगों को और परेशान कर रही थीं। साथ ही, खुले में मवेशी इसी सड़क पर गोबर किए हुए थे, जिससे गंदगी

और बढ़ गई थी। सोचिए, एक ईसान जो पहले से ही दुखी मन से अंतिम यात्रा के दौरान ऐसी जगह पहुँचता है, और वहाँ इस तरह की स्थिति देखकर मन में सिर्फ रहे राम, रक्षा करनार ही निकलता है। जब हम जीवित हैं, तो आइए इसानियत का फर्ज निभाएं, मूलभूत सुविधाएं दें, और सड़क सुरक्षा के प्रति नैतिक जिम्मेदारियाँ उठाएं। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें कि कहीं गड्डे न हों, और कहीं इस तरह से पानी जमा न हो। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा।

यह घटना फरीदाबाद में सड़क सुरक्षा और आधारभूत ढाँचे के प्रति हमारी लापरवाही का एक जीता जागता उदाहरण है। इसे अनदेखा करना और इसमें सुधार न करना, भविष्य में और अधिक समस्याओं को जन्म देगा। इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।



बरगढ़-नुआपाड़ा रेलवे लाइन को मिली कैबिनेट मंजूरी: मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड उडीशा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: बरगढ़ सांसद प्रदीप पुरोहित सहित पश्चिम ओडिशा के लोगों का लंबे समय से सपना पूरा होने जा रहा है। जल्द ही शुरू होगा बहुप्रतीक्षित बरगढ़-नुआपाड़ा रेल परियोजना। आज बरगढ़ सांसद प्रदीप पुरोहित की उपस्थिति में एक संवाददाता सम्मेलन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि 138 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन के लिए 2926 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस परियोजना में 47 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। विश्व प्रसिद्ध सम्बलपुरी साड़ी, भगवान नृसिंहनाथ का पीठ और ओडिशा का भातहाड़ी बरगढ़ को यह रेलवे लाइन जोड़ेगी, रेल मंत्री ने जानकारी दी। संवाददाता सम्मेलन में बरगढ़

सांसद प्रदीप पुरोहित ने कहा कि यह रेलवे लाइन पश्चिम ओडिशा के तीन पीढ़ियों के लोगों का सपना था। अब यह सपना पूरा होने जा रहा है। यह पश्चिम ओडिशा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की नई सौगात है, प्रदीप पुरोहित ने कहा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। बता दें कि कुछ दिन पहले बरगढ़ सांसद प्रदीप पुरोहित ने रेल मंत्री को नई रेलवे लाइन से संबंधित ज्ञापन सौंपा था। पश्चिम ओडिशा के आर्थिक, व्यावसायिक और व्यापारिक विकास के लिए यह रेलवे लाइन लाइफलाइन साबित होगी, उन्होंने ज्ञापन में कहा था। पदमपुर उप-चुनाव और पिछले आम चुनाव के दौरान रेल मंत्री ने इस रेल परियोजना के लिए प्रतिबद्धता जताई थी।



अब दुश्मनों की खैर नहीं, नौसेना को मिली अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी; चौंकाने वाली हैं खूबियां

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी गुरुवार को नौसेना को मिल गई। परमाणु शक्ति संपन्न 'आइएनएस अरिघात' को विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल किया गया। 'आइएनएस अरिघात' को भारत की नौसैनिक शक्ति और परमाणु प्रतिरोध क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी (एसएसबीएन- शिफ, सबमरीन, बैलिस्टिक, न्यूक्लियर) कार्यक्रम भारत की एक अत्यंत गोपनीय परियोजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ 'सह की मौजूदगी में नौसेना में शामिल की गई 'आइएनएस अरिघात' की लंबाई लगभग 112 मीटर है। अरिहंत की परियोजना जुलाई 2009 में शुरू

यह के-15 मिसाइलों से लैस है जिनकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। देश की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी 'आइएनएस अरिहंत' की परियोजना जुलाई 2009 में शुरू की गई थी और

2016 में उसका जलावतरण किया गया था।

83 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट-वाटर रिएक्टर दोनों पनडुब्बियों में 83 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट-वाटर रिएक्टर लगे हैं जिससे वे बिना ऊपर आए लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं। जबकि पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को नियमित अंतराल पर सतह पर आना पड़ता है। अचानक हुए हमले से बचने व जवाबी हमले करने की क्षमता के कारण एसएसबीएन प्रतिरोधक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुश्मन के लिए इनको तलाश कर पाना भी कठिन होता है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास लंबी दूरी की मिसाइलों वाली बड़ी एसएसबीएन हैं। उदाहरण के लिए चीन के पास छह जिन-क्लास एसएसबीएन हैं जो जेएल-3 मिसाइलों से लैस हैं। इनका निर्माण तीन चरणों में किया जाएगा

इन मिसाइलों की मारक क्षमता 10 हजार किलोमीटर तक है। अमेरिका के पास 14 ओहियो-श्रेणी की एसएसबीएन हैं। द्विचक्रालिक खरीद एवं क्षमता विकास रणनीति के तहत सरकार की योजना परमाणु



और पारंपरिक दोनों तरह की पनडुब्बियों के निर्माण की है। इसमें पांच अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियां और छह परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां शामिल हैं। इनका निर्माण तीन चरणों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति 6,000 टन की दो 'हंटर-किलर' एसएसएन (परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियां) के निर्माण के लिए लगभग 40 हजार करोड़ रुपये की परियोजना पर विचार कर रही है। ये टारपीडो, एंटी-शिप व लैंड-अटैक मिसाइलों से लैस होंगी। इनके निर्माण में एक दशक लगने की उम्मीद है।

ढालोप गांव में सीरवी समाज बंधुओ पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ पाली प्रशासन का महाघेराव

परिवहन विशेष न्यूज

देसुरी के ढालोप गांव में हुए सीरवी समाज बंधुओ पर जानलेवा हमले में लगभग 45 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण आज सम्पूर्ण सीरवी समाज द्वारा पाली प्रशासन मुख्यालय का महाघेराव किया गया जिसमें सीरवी नवयुवक मंडल परगना समिति विलाडा द्वारा 51 गाड़ियों का काफिला लेकर धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोगों का हजूम उमड़ पड़ा जिसमें अखिल भारतीय सीरवी महासभा अध्यक्ष और पाली सांसद पीपी चौधरी, जिला कलेक्टर लक्ष्मीनारायण मंत्री, पाली पुलिस अधीक्षक चतुराम जाट ने अखिल भारतीय सीरवी युवा परिषद की प्रमुख मांगों को लेकर देसुरी थाना के 3 स्टॉफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया और स्पेशल टीम द्वारा 72 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया तथा आरोपियों की बेमानी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। इस दौरान सीरवी नवयुवक मण्डल परगना समिति विलाडा के नेतृत्व में उक्त घटना क्रम को लेकर रोष



व्याप्त था तथा प्रशासन से सभी मांगों से आश्चर्य होकर सफल आयोजन के लिए महाघेराव में पधारे सभी सामाजिक



कार्यकर्ताओं और 36 कोम का साधुवाद के साथ सामाजिक एकता का जो बेमिसाल उदाहरण पेश किया है।

एक शाम गोगाजी के नाम भजन संध्या में बही भक्ति की सरिता

परिवहन विशेष न्यूज

स्थित तेजेश्वर महादेव मंदिर पुझल 12 खेड़ा जाट समाज के भीऊ परिवार चेन्नई द्वारा गोगा नवमी के उपलक्ष्य पर जागरण का आयोजन किया गया। जिसमें भजन गायक रमेश सीरवी मनली, आशुतोषसिंह कोडीगंयूर व स्थानीय भजन गायकों ने गणपति वंदना से जागरण का शुरुआत कर राजस्थानी लोक भजनों की एक से बढ़कर एक मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों पर श्रद्धालुओं भावविभोर होकर झुमते रहे। इस मौके पर 12 खेड़ा सचिव गणपति भीऊ, पूर्व कोषाध्यक्ष मांगीलाल भीऊ व समाज के गणमान्य पदाधिकारी पूर्व अध्यक्ष सचिव व वर्तमान अध्यक्ष कोषाध्यक्ष व समस्त कार्यकर्ताओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। चेन्नई में बसे भीऊ परिवार के प्रकाश, सोहनलाल, गोपाराम, पारसमल, शंकरलाल, पेमाराम, रिकबाम, जोराराम, मनीष, नैनाराम, राजेश, कमलेश, मदनलाल, चंपालाल,



मोहनलाल, मंगलाराम, के. अशोक, नरपत, गजेन्द्र, प्रवीण, मानकराम, राकेश, मोहनलाल, एम. भंवरलाल, अनोप, गोरधन, पवन, कानाराम एवं समस्त भीऊ परिवार व ईष्ट मित्रों के भाईयों ने हार्दिकता से साथ गोगा नवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर समाज के सभी युवा भाईयों ने शानदार व्यवस्था को संचारु रूप से सहयोग किया। यह जानकारी गणपति मांगीलाल भीऊ ने दी।

ट्रेनी IFS अधिकारियों ने पीएम मोदी से की भारत की विदेश नीति की प्रशंसा, प्रधानमंत्री से मांगा मार्गदर्शन

परिवहन विशेष

PM Modi आईएफएस के ट्रेनी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर भारत की विदेश नीति की सफलता की सराहना की। वहीं अधिकारियों ने पीएम से सुझाव पर उनका मार्गदर्शन मांगा। प्रधानमंत्री ने भी अधिकारियों के साथ सफलता के फेज साझा करते हुए कहा कि आप जहां भी तैनात रहें देश की संस्कृति का हमेशा ध्यान रखें। साथ ही उन्होंने और भी कई अहम बातें बताईं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आईएफएस के प्रशिक्षु अधिकारियों से चर्चा की और उन्हें बताया कि कैसे विश्व स्तर पर देश की धारणा बदल रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का भारत आपसी सम्मान और गरिमा के साथ समान

स्तर पर दुनिया के साथ संवाद करता है। पीएमओ की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, आईएफएस के 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने सुबह सात बजे लोक कल्याण मार्ग पर मोदी से मुलाकात की। इस बैच में 15 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 36 आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षण ले रहे हैं।

ट्रेनी अधिकारियों ने की भारत की विदेश नीति की प्रशंसा बयान में कहा गया कि प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विदेश नीति की सफलता की सराहना की और अपनी आगामी जिम्मेदारियों और इससे संबंधित कार्यों पर उनसे सुझाव और मार्गदर्शन मांगा। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि वह जहां भी तैनात रहें, उन्हें गर्व के साथ देश की संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए और जहां भी मौका

मिले उसका प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए।

मोदी ने अधिकारियों से व्यक्तिगत आचरण सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में औपनिवेशिक मानसिकता पर काबू पाने और इसके बजाय खुद को देश के गौरवशाली प्रतिनिधियों के रूप में पेश करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को बताया कि कैसे भारत ने अन्य देशों की तुलना में कोविड महामारी का मुकाबला किया।

पीएम ने दिया सुझाव उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने उन्हें यह भी सुझाव दिया कि वे विदेशों में अपनी तैनाती के दौरान भारतीय प्रवासियों के साथ अपने जुड़ाव का विस्तार करें।

